



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 57]

नई दिल्ली, बुधवार, मार्च 1, 1979/फाल्गुन 10, 1900

No. 57]

NEW DELHI, THURSDAY, MARCH 1, 1979/PHALGUNA 10, 1900

इस भाग में निम्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

वित्त मंत्रालय

(आर्थिक कार्य विभाग)

(बजट अनुभाग)

बजट 1979-80

उप-प्रधान मंत्री और वित्त मंत्री का भाषण

[सं० एफ० 18 (85)-बी० (डी०)/78]

नई दिल्ली, 28 फरवरी, 1979

महोदय,

मैं 1979-80 का बजट पेश करने के लिए उपस्थित हुआ हूँ।

2. चालू वर्ष के दौरान अर्थ-व्यवस्था की जो प्रवृत्तियाँ रही हैं उनका विस्तृत विवरण कुछ दिन पहले सदन में प्रस्तुत की गई 1978-79 की "आर्थिक समीक्षा" में दिया गया है। इसलिए मैं अपने विचारों को आर्थिक स्थिति के ऐसे कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं तक ही सीमित रखूँगा जिनके मन्दर्भ में यह बजट तैयार किया गया है।

3. चालू वर्ष के दौरान भारतीय अर्थ-व्यवस्था की प्रगति बहुत सन्तोषजनक रही है। कृषि का उत्पादन लगातार दूसरे वर्ष फिर सर्वोच्च स्तर (रेकार्ड लेवल) पर हुआ है। यह सफलतापूर्ण रूप से अनुकूल मौसमी कारणों से ही नहीं मिली है। उत्पादन बढ़ने का एक काफी बड़ा कारण यह भी रहा कि मिचलाई और उर्वरक अधिक मात्रा में उपलब्ध हुए, उन्नत बीजों का इस्तेमाल किया गया, अनुसंधान और विस्तार सम्बन्धी कार्य-कवाप में वृद्धि की गई और कीमत समर्थन (प्राइस सपोर्ट) तथा अनाज की खरीद का काम बढ़ाया गया। यह प्रगति काफी हद

तक उन लाखों किसानों की तानक और मेहनत की बदौलत हुई है जिन्होंने इन कार्यों में अपनी पूँजी लगाई है, नई प्रौद्योगिकी (टेक्नोलॉजी) का इस्तेमाल किया है, खेती के नए तरीके अपनाए हैं और एक की जगह दो बालियाँ पैदा करके सर्वसामान्य के हित में योगदान दिया है।

4. जब तक देश में, खासतौर से बेहाली इलाकों में, बहुत ज्यादा गरीबी और बेरोजगारी फैली हुई है और जब तक खेती में रोजगार पैदा करने और अधिकांश लोगों को कय-शक्ति प्रदान करने की सबसे अधिक क्षमता है, तब तक खेती के सुधार के काम में कोई ढिलाई नहीं बरती जा सकती। हमारा उद्देश्य यह होना चाहिए कि हम उन्नत प्रौद्योगिकी और कृषि उपयोगी वस्तुओं का अधिक इस्तेमाल करके उत्पादकता को और ज्यादा बढ़ाएं। इसके लिए अधिक पूँजी निवेश (इन्वेस्टमेंट), बड़े पैमाने पर तरह-तरह के प्रयत्न और बेहतर संगठन की जरूरत है।

5. आशा है कि चालू वर्ष के दौरान औद्योगिक उत्पादन में भी 7 से 8 प्रतिशत की वृद्धि होगी। यह बहुत-से उद्योगों के उत्पादन में सुधार होने से सम्भव हुआ है। खासतौर से, बिजली उत्पादन, खाद्य उद्योगों, धातु उत्पादों, बिजली की और बगैर बिजली की मशीनों, वस्त्रों और परिवहन उपकरण के उत्पादन में तेजी से वृद्धि हुई है। सीमेंट, उर्वरक, हस्पात और अलौह धातुओं जैसी बुनियादी वस्तुओं की कुल उपलब्धि को बड़ी मात्रा में आयात के द्वारा बढ़ाया गया ताकि इन वस्तुओं की कमी के कारण देश के विकास में कोई बाधा उपस्थित न हो।

6. यदि आने वाले वर्ष में भी कृषि और उद्योगों के उत्पादन में इसी दर से वृद्धि करते रहना है तो अधिक पूँजी निवेश करने बुनियादी वस्तुओं को अधिक मात्रा में उपलब्ध कराना होगा। इसीलिए सरकार

निर्वाह, विजली उत्पादन, सीमेंट, इस्पात, उर्वरक और परिवहन में भारी पूंजी निवेश के कार्यक्रम के साथ आगे बढ़ रही है।

7. सरकार पिछले साल की तरह इस साल भी कीमतों में स्थिरता बनाए रख सकी है। 10 फरवरी, 1979 को थोक कीमतों का सूचक संक, एक साल पहले के स्तर से, केवल 0.9 प्रतिशत और दो साल पहले के स्तर से 0.4 प्रतिशत ऊपर था। एक ऐसी अवधि में जबकि राष्ट्रीय आय में लगभग 11 प्रतिशत की वृद्धि हुई हो, कीमतों में इतनी अधिक स्थिरता रख पाने का रेकार्ड दुनिया में और कहीं मिलना कठिन होगा। यह स्थिरता पूँजी और मांग के प्रबन्ध की सुविचारित नीतियों के जरिये प्राप्त की जा सकी है। इस सम्बन्ध में यह बताना भी जरूरी है कि बड़े हुए कृषि और औद्योगिक उत्पादन तथा महत्वपूर्ण क्षेत्रों के लिए अपनई गई उदार आयात नीति ने भी महत्वपूर्ण भूमिका भूमा की है। साथ ही एक ऐसी मौद्रिक नीति का पालन किया गया है जो ऋण के प्रवाह को अर्थ-व्यवस्था में सट्टेबाजी की गतिविधियों की ओर जाने से रोकती है और ऋण को उत्पादक क्षेत्रों की ओर प्रवाहित करती है।

8. पूंजी निवेश के कार्यक्रम को बढ़ाने के लिए साधनों को बढ़ाना भी जरूरी है। परन्तु ऐसा प्रतीत होता है कि साधनों का संग्रह आवश्यकताओं के अनुकूल नहीं हो रहा है। सरकार को अर्थ-व्यवस्था के कई क्षेत्रों में ऐसी प्रवृत्ति दिखाई देती है कि वे कर सम्बन्धी रियायतों को अपनी घटती हुई दौलत को बढ़ाने का एकमात्र तरीका मानते हैं। यह समझ लेना चाहिए कि अगर विकास के लिए आवश्यक साधनों को, मुद्रास्फीति (इन्फ्लेशन) के बिना, जुटाना है तो उन लोगों को करों का अधिक बोझ उठाने के लिए तैयार रहना चाहिये जिनमें इस बोझ को उठाने की सामर्थ्य है।

9. साधन जुटाने के एक दूसरे माध्यम से भी प्रत्याशित सफलता नहीं मिली है। सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों का अधिशेष (सरप्लस) 1977-78 में अनुमान से काफी कम रहा। ऐसा प्रतीत होता है कि चालू वर्ष में भी उनके अधिशेष की मात्रा बहुत ज्यादा नहीं होगी। इस बात को ध्यान में रखते हुए कि इन उद्यमों में कुल 12,800 करोड़ रुपए की पूंजी लगाई गई है, यह स्थिति वास्तव में निराशाजनक है।

10. यदि बढ़ते हुए पूंजी निवेश के लिए वित्त की व्यवस्था अस्फीतिकारी (नॉन इम्प्लेशनरी) तरीके से करनी है तो अर्थ-व्यवस्था में और अधिक बचतें करनी होंगी। इस कार्य में सफलता अन्य बातों के साथ-साथ, अपव्यय को, चाहे वह सरकारी क्षेत्र में हो या निजी क्षेत्र में, कम करके प्राप्त की जा सकती है। विकास-भिन्न व्यय को, और खास तौर से ऐसी आर्थिक सहायता (सब्सिडी) के व्यय को सीमित करके, जो कोई खास सामाजिक या आर्थिक प्रयोजन सिद्ध नहीं करती, सरकारी व्यय में किरफायत की जा सकती है। विलास व्यय पर निष्ठुरतापूर्वक संकुश लगाकर हमारे आर्थिक जीवन के कठोर तथ्यों और हमारे परम्परागत जीवन मूल्यों के अनुरूप अधिक सावसीपूर्ण जीवन जैसी अपनाकर निजी बचतों को बढ़ाया जाना चाहिए।

11. निर्यात में 1977-78 से पहले के तीन वर्षों में गतिशील वृद्धि हुई थी लेकिन उसमें चालू वर्ष के पहले छठ महीनों में वस्तुतः कमी हुई है। यह चिन्ताजनक प्रवृत्ति कई कारणों से आई है जैसे, आयात-कर्ता देशों में हमारी अधिक गतिशील मर्चों पर लगाए गए प्रतिबन्ध, विकसित देशों में मन्दी की प्रवृत्तियाँ और कुछ निर्यात योग्य वस्तुओं की आन्तरिक मांग में वृद्धि। यह बहुत जरूरी है कि हम एक सक्रिय निर्यात संवर्द्धन नीति का पालन करके कुल निर्यात में जो गिरावट की प्रवृत्ति है उसे उलट दें।

12. विनिर्मित वस्तुओं के निर्यात को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर बल देने के साथ-साथ, हमें इस बात को भी नजरअन्दाज नहीं करना चाहिए कि एक बड़ा कृषि-प्रधान देश होने के नाते उत्पादों (प्रोडक्ट) के निर्यात को बढ़ाने के लिए भी एक सक्रिय नीति अपनाने की आवश्यकता है। एक ऐसी नीति का तत्परता से पालन करने की जरूरत है जिससे फल, सब्जियाँ, कुछ किस्मों के वनस्पति तेल, तेलजन्य पदार्थ और गरम मसाले जैसी वस्तुओं की आवश्यकता से अधिक मात्रा को निर्यात के लिए बढ़ाया जाए क्योंकि ऐसा करने से न केवल किसानों की आय बढ़ेगी बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में अतिरिक्त रोजगार भी पैदा होगा।

13. आयात के बढ़ते हुए स्तर से पता चलता है कि विकास के लिए प्रारंभित निधि (रिजर्व) के उपयोग को प्रक्रिया शुरू हो गई है। खाद्य तेल जैसी उपभोग्य वस्तु के आयात के अलावा, इस्पात, सीमेंट, उर्वरक और अल्यूमीनियम धातु जैसी विकासात्मक वस्तुओं का आयात भी काफी ज्यादा बढ़ गया है। आयात नीति को उदार बना दिया गया है और जहाँ कहीं आवश्यक था आयात मुक्तों को कम कर दिया गया था एकवम हटा दिया गया है ताकि पूंजीगत वस्तुओं, फासल, पुर्णों, संघटकों (कॉम्पोनेन्ट) और कच्ची सामग्री का आयात करने में सुविधा हो और इस प्रकार उत्पादन और निवेश में आने वाली कठिनाइयों को दूर किया जा सके।

14. देश के विदेशी मुद्रा के प्रारंभित भण्डार में वृद्धि की दर चालू वर्ष के दौरान धीमी पड़ गई है। ऐसा अंशतः निर्यात और आयात की प्रवृत्तियों के कारण और अनुष्य प्राप्तिवों की वृद्धि की दर कम हो जाने के कारण हुआ है। यदि हम विभिन्न राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय घटनाओं पर वृष्टिगत करें तो हमें मान्य होगा कि हम इसमें लगातार वृद्धि की आशा नहीं कर सकते। इसलिए, यद्यपि इस समय तो हमारे विदेशी मुद्रा के भण्डार का स्तर ऊँचा है फिर भी इसमें से सम्भवकर खर्च करने की जरूरत है।

1978-79 के संशोधित अनुमान

15. मैं 1978-79 के संशोधित अनुमानों पर आता हूँ।

16. जहाँ तक व्यय का सम्बन्ध है, बजट के बाद ऐसी कई घटनाएँ घटी जिनके कारण चालू वर्ष में केन्द्र पर अतिरिक्त बोझ आ पड़ा।

17. जैसा कि सम्मानित सदस्य जानते हैं, हाल के वर्षों में लगातार कई राज्य सरकारें रिजर्व बैंक से अपनी उधार लेने की हकबारी से ज्यादा रकम निकालती रही हैं। इस उद्देश्य से कि राज्य साफ हिसाब के साथ शुद्धात करें और भविष्य में भी ओवरड्राफ्ट न लें, हमने राज्यों को 1977-78 के अन्त तक के ओवरड्राफ्ट चुकाने करने के लिए विशेष ऋण देने का निर्णय किया था। इस सम्बन्ध में की गई प्रयासियों की राशि 555 करोड़ रुपए की है। दैवी विपत्तियों से पीड़ित लोगों को अनुग्रहपूर्ण राहत देने के लिए राज्यों को दी जाने वाली सहायता की 10 करोड़ रुपए की मूल राशि को बढ़ाकर 40 करोड़ रुपए करना पड़ा।

18. किसानों को उनकी उपज पर ज्यादा ग्रामवसी देने के लिए चालू वर्ष के दौरान खाल, गेहूँ और मोटे धानाओं की बसूली कीमत (प्रोक्योरमेन्ट प्राइस) को बढ़ाया गया जिसके कारण लगभग 42 करोड़ रुपए का अतिरिक्त व्यय हुआ। भारतीय खाद्य निगम को भद्रा की गई कुछ बकाया रकमों और विमम्बर, 1978 से गेहूँ की निर्गम कीमत (शुल्क प्राइस) में वृद्धि करने से हुई अधिक प्राप्तिवों को हिसाब में लेने के बाद, चालू वर्ष के दौरान खाद्य सम्बन्धी आर्थिक सहायता के अन्तर्गत बजट अनुमानों की 456 करोड़ रुपए की राशि के अलावा 114 करोड़ रुपए का अतिरिक्त व्यय होगा।

19. निर्यात सहायता के व्यय में, 251 करोड़ रुपए की बजट व्यवस्था के अलावा, 130 करोड़ रुपए की वृद्धि होगी जिसका आंशिक कारण यह

है कि पिछले वर्ष के बचे हुए ढावों की काफी अधिक रकम इस वर्ष चुकानी पड़ी। 1978 में 6.5 लाख मेट्रिक टन चीनी के निर्यात पर होने वाली हानि, 10 करोड़ रुपए की मूल व्यवस्था से 23 करोड़ रुपए ज्यादा होगी।

20. आयोजना-भित्त सहायता के रूप में ऐसे बहुत से सरकारी क्षेत्र के एककों को बजट में प्रत्याशित राशि में अधिक सहायता देनी पड़ी जिन्हें उत्पादन में हुई हानियों के कारण वित्तीय कठिनाइयाँ महसूस हुईं। कोन इण्डिया को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ और उसे, 90 करोड़ रुपए की व्यवस्था के मुकाबले में, 173 करोड़ रुपए की सहायता की आवश्यकता होगी। उर्वरक निगम और राष्ट्रीय वस्त्र निगम जैसे कुछ और उपक्रमों को भी काफी मात्रा में अतिरिक्त सहायता की जरूरत है। इसके परिणामस्वरूप सरकारी उपक्रमों को दिए जाने वाले आयोजना-भित्त ऋणों की राशि 250 करोड़ रुपए की बजट व्यवस्था से केवल 159 करोड़ रुपए अधिक हो जाएगी।

21. चूंकि अल्प बचतों से प्रत्याशित से अधिक राशि प्राप्त हुई है इसलिए इस संग्रह में से राज्य सरकारों को उनके हिस्से के रूप में दिए जाने वाले ऋणों की राशि 300 करोड़ रुपए की बजट व्यवस्था से 165 करोड़ रुपए ज्यादा होगी, इस में से कुछ वृद्धि पिछले वर्ष के आखिरी वित्तों में संग्रह की राशि में तेजी से बढ़ोतरी होने के कारण हुई।

22. अनुमान है कि चालू वर्ष में रक्षा व्यय, 2945 करोड़ रुपए की बजट व्यवस्था के मुकाबले में, 2845 करोड़ रुपए का होगा।

23. केन्द्रीय आयोजना व्यय की स्थिति एक-जैसी नहीं रही है और कुल मिलाकर केन्द्रीय आयोजना व्यय के लिए निर्धारित 4520 करोड़ रुपए की व्यवस्था में से 201 करोड़ रुपए कम खर्च होने का अनुमान है। मुख्य रूप से पेट्रोलियम, उर्वरक और दूर-संचार परियोजनाओं में अनुमानित अधिक कमी होगी। तेल और प्राकृतिक गैस आयोग को अपने धन-तट कार्यक्रम (ऑफ शोर प्रोग्राम) के कुछ तर्माण-कार्यों को स्थगित करने या उन्हें नए सिरे से चरणबद्ध करने के कारण, 63 करोड़ रुपए की कम जरूरत होगी। पेट्रोलियम क्षेत्र के परिचय में कमी होने के कारण तेल उद्योग विकास बोर्ड को भी 58 करोड़ रुपए की कम जरूरत होगी। उर्वरक परियोजनाओं के लिए भी 236 करोड़ रुपए की मूल व्यवस्था की तुलना में, 36 करोड़ रुपए की कम जरूरत होगी; यह कमी खास तौर से ट्राम्बे V और कोचीन चरण II के एककों और महाराष्ट्र में स्थापित किए जाने वाले गैस पर आधारित नए उर्वरक संयंत्र के सम्बन्ध में हुई है। अनुमान है कि दूर-संचार परियोजनाओं का परिचय, जिसकी वित्त व्यवस्था अधिकतर आन्तरिक साधनों से की जाती है, मुख्य रूप से उपस्कर (इक्विपमेंट) और सामान की प्राप्ति में हुई बेरी के कारण, 46 करोड़ रुपए कम होगा।

24. कृषि की योजनाओं में 25 करोड़ रुपए कम खर्च होने का अनुमान है। राज्य सरकारों द्वारा कार्यान्वयन में या व्योरेवार योजनाएं तैयार करने में देरी किए जाने के कारण और आवश्यक आधारभूत सुविधाओं की अपर्याप्तता की वजह से, कुछ कृषि योजनाओं के कार्य में आवश्यक तेजी नहीं आ सकी है। इन समस्याओं को मुलमाया आ रहा है। किन्तु कुछ योजनाओं में अच्छी प्रगति हुई है। सम्मानित सदस्यों को यह जानकर खुशी होगी कि 'काम के बखले अनाज' कार्यक्रम ग्रामीण विकास और रोजगार संचर्दन का एक बड़ा साधन बन रहा है और हम योजना के लिए जो 30 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई थी उसे बढ़ा कर 100 करोड़ रुपए कर दिया गया है और धाया है कि इससे वर्ष में 40 करोड़ श्रम-वित्तों का काम पैदा होगा। डेरी विकास कार्यक्रम को जिससे देहाती इलाकों में लाभपूर्ण रोजगार भी मिलेगा और ग्राम में बढ़ोतरी भी होगी, 11 करोड़ रुपए की बजट व्यवस्था से 19 करोड़ रुपए ज्यादा दिये गये हैं।

25. चालू बजट में राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों की आयोजनाओं को सहायता देने के लिए 2761 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई थी। जैसा कि सम्मानित सदस्यों की मांग है, इस साल जो राज्य बाढ़ों से पीड़ित हुए थे, उनके साधनों में भी गंभीर रूप से कमी हो गई और वे केन्द्र से अतिरिक्त सहायता प्राप्त किए बिना अपनी अनुमोदित आयोजनाओं के परिचय की वित्त व्यवस्था करने की स्थिति में नहीं थे। इसलिए उन राज्यों को 325 करोड़ रुपए की अतिरिक्त आयोजना-सहायता देना जरूरी हो गया था। ग्रामीण विस्तृतीकरण मिश्रण को भी उसकी राज्य-क्षेत्र की अनुमोदित आयोजनागत योजनाओं की वित्त-व्यवस्था करने के लिए बजट से 39 करोड़ रुपए ज्यादा देने पड़े। संग्रहित अनुमानों के अनुसार चालू वर्ष में राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों के लिए केन्द्रीय सहायता राशि 3112 करोड़ रुपए बैठती है।

26. जहां तक चालू वर्ष में प्राप्तियों का संबंध है, अल्प बचतों के संग्रह से, 460 करोड़ रुपए के बजट अनुमानों की अपेक्षा, 140 करोड़ रुपए अधिक प्राप्त होंगे; इसका श्रेय केन्द्र और राज्यों की संबद्ध एजेंसियों को जाता है जिन्होंने इस विश्वास में सतत प्रयत्न किए हैं। अनुमान है कि गैर-सरकारी भविष्य निधियों की जमा-राशियों में भी, 225 करोड़ रुपए के बजट अनुमानों से 75 करोड़ रुपए की अधिक वृद्धि होगी। सोने की बिक्री से, जिसे बजट बनाते समय हिसाब में नहीं लिया गया था, 88 करोड़ रुपए की प्राप्ति हुई है। द्विपक्षीय व्यापार करने वाले देशों को पहले के वर्षों में जो अल्पकालीन ऋण दिए गए थे उनकी वसूलियों में भी उन देशों से अधिक आयात होने के कारण, 75 करोड़ रुपए की वृद्धि होगी।

27. इस वर्ष देश के पूर्वी भाग में बाढ़ें आ जाने से औद्योगिक उत्पादन अस्तव्यस्त हो जाने के कारण और सरकारी क्षेत्र के कुछ बड़े उपक्रमों के लाभ के मार्जिन में कमी हो जाने की वजह से निगम और प्राय करों की प्राप्तियों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। ये प्राप्तियां, 2577 करोड़ रुपए के बजट अनुमानों से, लगभग 102 करोड़ रुपए कम होने का अनुमान है। संघ उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क से कुल मिला कर 145 करोड़ रुपए अधिक प्राप्त होंगे। आयात नीति को उदार बना देने और देश की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अधिक आयात करने के फलस्वरूप, धाया है कि सीमाशुल्कों में, 1860 करोड़ रुपए के बजट अनुमानों से, 250 करोड़ रुपए की अधिक प्राप्ति होगी लेकिन, दूसरी ओर, संघ उत्पादशुल्कों के रूप में, 5299 करोड़ रुपए के बजट अनुमानों से, 105 करोड़ रुपए कम प्राप्त होंगे। इस कमी का कारण, अन्य बातों के साथ साथ, यह भी रहा है कि खांडसारी पर से शुल्क हटा लिए जाने के कारण और चीनी का कंट्रोल समाप्त कर देने के बाद उसकी कीमतों में गिरावट आ जाने की वजह से चीनी पर कम शुल्क प्राप्त हुआ है। मिट्टी के तेल (किरोसीन), मर्निक्-निर्मित रेजे, एल्युमिनियम और ताम्बे से भी कम उत्पाद-शुल्क राजस्व प्राप्त हुआ है किन्तु इन वस्तुओं पर अपेक्षाकृत अधिक आयात-शुल्क प्राप्त हो जाने से इस कमी की अधिपूति हो गई है।

28. विदेशी सहायता का उपयोग भी कम हुआ है; इसका एक कारण यह है कि वस्तुओं का आयात देने वाली एजेंसियों ने कार्यक्रम की बजट परियोजना के लिए सहायता देना शुरू कर दिया है और दूसरा कारण यह है कि कुछ देशों से द्विपक्षीय सहायता का अधिक बड़ा भाग विशिष्ट परियोजनाओं के लिए दिया जाने लागा है। दोनों स्थितियों में, संबद्ध परियोजनाएं धीमी चल रही हैं और इसलिए सकल सहायता प्राप्तियां बजट अनुमानों की अपेक्षा 447 करोड़ रुपए कम होगी। तथापि, भुगतानों की गति को तेज करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं।

29. प्राप्तियों और व्यय में हुए अन्य परिवर्तनों को हिसाब में लेने पर अनुमान है कि चालू वर्ष में कुल मिलाकर 1590 करोड़ रुपए का घाटा रहेगा जबकि मूल अनुमान 1071 करोड़ रुपए का था। इसमें 555 करोड़ रुपए की वह अतिरिक्त राशि शामिल नहीं की गई है जिसका बोझ, कुछ राज्यों

की उनके पिछले षाटे को पूरा करने के लिए बिए गए ऋणों के रूप में, केन्द्र पर डाला गया था और जो खाता-समायोजन (बुक एडजस्टमेंट) के रूप में होने के कारण, चालू वर्ष में कोई आर्थिक प्रभाव नहीं डालेगा।

1979-80 के लिये बजट अनुमान

30. अब मैं 1979-80 के लिए व्यय के अनुमान पेश करूंगा।

31. इस बजट में सातवें वित्त आयोग की उन सिफारिशों का प्रभाव प्रतिबिम्बित होता है जो सरकार द्वारा स्वीकार कर ली गई हैं। हालांकि हमारी संघीय शासन व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए आयोग के पंचाट (एवांठ) के अनुसार राज्यों को अधिक साधन प्रदान करना अत्यन्त वांछनीय है तथापि इससे अत्यधिक भ्रष्टाचार के लिए गम्भीर वित्तीय समस्याएं उत्पन्न हो जाएंगी। इस बजट में इन समस्याओं से निपटने का प्रयास किया गया है।

32. केन्द्र, राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों की 1979-80 की वार्षिक आयोजना, 1978-79 के 11649 करोड़ रुपये के कुल अनुमोदित परिचय की तुलना में, 12511 करोड़ रुपये की होगी। यह राशि 7.4 प्रतिशत वृद्धि की ओरतक है। किन्तु, इस राशि का निर्धारण करते समय सम्मानित सचिव इस बात को ध्यान में रखेंगे कि केन्द्रीय और राज्यों की आयोजनाओं में 835 करोड़ रुपये की अनुमानित राशि वृद्धि व्यय के रूप में आयोजना-व्यय से आयोजना-मिश्र व्यय में अन्तर्गत कर दी गई है। इस अन्तर्गत को हिसाब में लेते से, 1979-80 के विकास व्यय में उल्लेखनीय वृद्धि हो जाएगी।

33. 1979-80 के बजट में केन्द्रीय आयोजना के लिए और राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों की आयोजनाओं को सहायता देने के लिए 7108 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। राज्यों की आयोजनाओं, संघ राज्य क्षेत्रों की आयोजनाओं और पहाड़ी तथा जन-जातीय क्षेत्रों की उप-आयोजनाओं, उत्तर-पूर्व परिषद और ग्रामीण विद्युतीकरण निगम की योजनाओं के परिचय के लिए केन्द्रीय सहायता देने के उद्देश्य से 2300 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। राज्यों, संघ राज्य क्षेत्रों उत्तर-पूर्व परिषद आदि की आयोजनाएं, उनके अपने साधनों समेत, 1979-80 में कुल मिला कर 6099 करोड़ रुपये की होगी जबकि 1978-79 में इनके परिचय के लिए 5885 करोड़ रुपये रखे गए थे।

34. केन्द्रीय आयोजना के लिए बजट में 4808 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। इस प्रकार सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के 1604 करोड़ रुपये के आन्तरिक और अन्य साधनों को मिला कर, 1979-80 की केन्द्रीय आयोजना 6412 करोड़ रुपये की होगी जबकि वह -1978-79 में 5864 करोड़ रुपये की थी।

35. 1979-80 की केन्द्रीय आयोजना और राज्यों की आयोजनाओं के लिए परिचयों का निर्धारण कर दिए जाने के बाद, राष्ट्रीय विकास परिषद की हाल की बैठक में, केन्द्र-प्रायोजित योजनाओं के सम्बन्ध में कुछ फेर-बदल करने का निर्णय लिया गया है। कुछ केन्द्र-प्रायोजित योजनाओं के लिए जो धन-राशियां अब आवंटित की गई हैं वे एक नए फार्मूले के आधार पर राज्यों में वितरण के लिए दी जाएंगी। इन योजनाओं के लिए 1979-80 की बजट व्यवस्थाओं में वर्ष के दौरान तदनुसार समायोजन किए जाएंगे।

36. जैसा कि सम्मानित सदस्य जानते हैं, हमारी नई विकास नीति का बुनियादी उद्देश्य गरीबी और बेरोजगारी को मिटाना है। इसके लिए हमारी आयोजनाओं में प्राथमिकताओं के क्रम में ग्रामीण परिवर्तन करने की आवश्यकता है। इसलिए हमारी आयोजनाओं में कृषि और ग्रामीण विकास को सर्वोच्च स्थान दिया गया है। लेकिन सरकार यह मानती है कि अथेक्षित सीमा तक, विकास आयोजनाओं को नई विधा काफी सम्बन्ध में ही

दी जा सकती है। तथापि हम उन कार्यक्रमों की गति और प्रभाव को तेजी से बढ़ाना चाहते हैं, जिनका, कृषि का विकास करने और रोजगार बढ़ाने से अनिष्ट सम्बन्ध है।

37. कृषि और ग्रामीण विकास के आयोजना परिचय को, जो 1978-79 में 1754 करोड़ रुपये का था, बढ़ाकर 1979-80 में 1811 करोड़ रुपये कर दिया गया है। 2000 ऐसे खण्डों (ब्लॉक) में जहाँ विशेष कार्यक्रमों में से कोई एक कार्यक्रम चल रहा हो और 300 अन्य खण्डों में जहाँ अब तक ऐसा कोई विशेष कार्यक्रम नहीं चल रहा हो, एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम में तेजी लाने के लिए 258 करोड़ रुपये के परिचय की व्यवस्था की गई है। जोर इसी बात पर दिया जाएगा कि छोटे और सीमांत किसानों, खेतिहर मजदूरों, ग्रामीण कारीगरों और अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन-जातियों की आर्थिक दशा में सुधार किया जाए। 'काम के बदले भ्रान्त' कार्यक्रम के लिए 50 करोड़ रुपये की व्यवस्था की जा रही है। चालू वर्ष के दौरान अनुभव को देखते हुए मुझे, निःसंवेह इस राशि को बहुत ज्यादा बढ़ाना होगा। लेकिन इस वृद्धि से कोई मुद्रास्फीतिकारी प्रभाव नहीं पड़ेगा क्योंकि हम इसके लिए अपने संचित खाद्यान्न भंडारों का ही सहारा लेंगे।

38. सरकार को इस सदन में इस बात पर जोर देने की जरूरत नहीं होगी कि कृषि विकास के लिए सिंचाई का बहुत महत्व है। बाढ़ नियन्त्रण अहित बड़ी, मध्यम और छोटी सिंचाई परियोजनाओं के परिचय के लिए 1979-80 में 1488 करोड़ रुपये की व्यवस्था की जा रही है जबकि 1978-79 में 1401 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई थी। इसमें से अधिकांश परिचय राज्य सरकारों के बजटों में शामिल किया जाएगा। 1979-80 में 32 लाख हेक्टेयर की अनिश्चित सिंचाई की क्षमता बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है जबकि 1978-79 में 28 लाख हेक्टेयर का लक्ष्य रखा गया था। छोटी सिंचाई के विकास की गति को तेज करने लिए छोटी सिंचाई पर जोर देने वाली आर्थिक सहायता को जो इस समय केवल छोटे और सीमान्त किसानों के लिये ही उपलब्ध है, उन किसानों को भी लेकिन घटी दर पर, उपलब्ध करने के लिए एक योजना बनाई जा रही है जिनके पास 2 से 4 हेक्टेयर के बीच जमीन है। इस उद्देश्य से 10 करोड़ रुपये की व्यवस्था की जा रही है। छोटी सिंचाई के कार्यक्रम के लिए निर्धारित आयोजनागत व्यवस्था की अनुपूर्ति करने के लिए कृषि पुनर्वित्त और विकास निगम के साधन उपलब्ध कराए जाएंगे। केन्द्रीय बजट से कृषि पुनर्वित्त और विकास निगम को उपलब्ध की जाने वाली वित्तीय सहायता को, जो 1978-79 में 133 करोड़ रुपये की थी, बढ़ाकर 1979-80 में बढ़ाकर 159 करोड़ रुपये कर दिया गया है।

39. हम ग्रामीण विकास और ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार प्रदान कार्यक्रमों का जो अत्यन्त महत्व दे रहे हैं, उसी के संवर्धन में यह सुनिश्चित करना जरूरी है कि आने वाले वर्षों में ग्रामीण क्षेत्रों की और संस्थागत वित्त का प्रवाह सुचारू तथा नियमित रूप से और व्यापक की उचित दरों पर हो। पहले उठाए गए कदमों के अलावा सरकार ने कृषि पुनर्वित्त और विकास निगम को जो कि कृषि के लिए आर्थिक ऋणों के सम्बन्ध में पुनर्वित्त को व्यवस्था करने वाली प्रमुख एजेंसी है, आग्रह से मुक्त कर देने का फैसला किया है। हम जो हमारे उपाय मोक्ष रहे हैं उनके साथ मिलकर इन रियायत से कृषि पुनर्वित्त और विकास निगम अद्यतन की उस दर को लगभग एक प्रतिशत कम कर सकेंगे जिस पर वह छोटी सिंचाई और भूमि विकास के लिए ऋणों को पुनर्वित्त व्यवस्था करता है; रिजर्व बैंक भी यह सुनिश्चित करने के लिए तत्पर है कि उठाएगा कि व्यापक की दर में लगभग एक प्रतिशत की कमी किए जाने का सम्पूर्ण लाभ वाणिज्यिक बैंकों द्वारा अग्रिम ऋणकर्ता (ग्रुटीमेट ब्रोकर) तक पहुंचा दिया जाए। इसके फलस्वरूप, किसानों को छोटी सिंचाई और भूमि विकास में पूंजी लगाना सस्ता पड़ेगा और इसलिए अधिक आकर्षक दिखाई देगा।

40. सम्मानित सचिव इस बात से अवगत हैं इस वर्ष शुरू की ग्रामीण विकास के कार्यक्रम के एक भाग के रूप में प्रीपैरेशन प्लान II नामक एक राष्ट्रीय डेरी विकास कार्यक्रम को अनुमोदित किया गया था जिसका उद्देश्य जनता

के प्रोषण स्तर को ऊँचा उठाना, रोजगार पैदा करना और एक सक्षम सहायक धन्य के जरिये से ग्रामीण क्षेत्रों में आय को बढ़ाना है। इस कार्यक्रम के लिए 1979-80 की केन्द्रीय आयोजना में 32 करोड़ रुपये के परिचय की व्यवस्था की गई है। इस कार्यक्रम के पूरा हो जाने पर इस से एक करोड़ किसान परिवारों का लाभपूर्ण रोजगार मिलेगा और हमारी जनता को अधिक दूध की उपलब्धि सुनिश्चित हो जाएगी।

41. गांवों में बिजली लगाने का कार्यक्रम हमारे कृषि और अर्थ-विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। ग्राम विद्युतीकरण कार्यक्रम के लिए 1979-80 में 285 करोड़ रुपये के कुल परिचय की व्यवस्था की जाएगी। इसके अलावा 50 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि इस प्रयोजन के लिए वार्षिक बजटों, कृषि पुनर्वित्त और विकास निगम तथा ग्रामीण विद्युतीकरण निगम के माध्यम से जुटाई जाएगी। 1978-79 में इसके तुलनीय अंकड़ क्रमशः 277 करोड़ रुपये और 20 करोड़ रुपये के हैं। अनुमान है कि 1978-79 में 22000 गांवों में बिजली लग जाएगी, और इसकी तुलना में 1979-80 में 25000 गांवों का लक्ष्य रखा गया है।

42. खेती की पैदावार बढ़ जाने से यह स्पष्ट है कि उत्तरी भंडारण क्षमता (स्टोरेज) को बढ़ाने की भी जरूरत होगी जिससे की भनाज की कम से कम बरबादी हो। इसलिए ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक सहायता देकर भंडारण की सुविधाएं उपलब्ध करने के लिए एक योजना तैयार की जा रही है। इससे बोहरा लाभ होगा भनाज उत्पादन के स्थानों के पास ही गोवामों में रखा जा सकेगा जिससे बरबादी कम होगी; और सरकार को भी भंडारण का कम खर्च उठाना पड़ेगा क्योंकि गोदाम भी सस्ते में बन सकेंगे और भनाज के भंडार को रखने का खर्च भी किसान ही उठायेंगे।

43. यह सरकार ग्रामीण जलपूर्ति के कार्यक्रमों को शीघ्र पूरा करने के लिए बचनबद्ध है जिससे की सभी समस्याग्रस्त गांवों में निरापव और विश्व-सनीय पीने का पानी उपलब्ध हो सके। 1979-80 की केन्द्रीय आयोजना में इस कार्यक्रम के लिए 80 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है जबकि 1978-79 में इसके लिए 60 करोड़ रुपये निर्धारित किए गए थे। मार्च 1977 में इस सरकार के सत्ता में आने के बाद से 1978-79 में 18,000 गांवों में पीने के पानी की व्यवस्था की गई थी। 1978-79 के लिए 27,000 गांवों का लक्ष्य रखा गया है। मैं सदन को यह विश्वास दिलाता चाहूंगा कि अगर इन कार्यक्रमों में और ज्यादा तेजी से प्रगति हुई तो सरकार इस प्रयोजन के लिए और धन राशि देने में नहीं हिचकिचाएगी।

44. अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों का आर्थिक प्रोषण और उनके प्रति सामाजिक भेदभाव तब तक खत्म नहीं होगा जब तक कि उनके विकास के कार्यक्रम ठोस आर्थिक आधार पर नहीं चलाए जाते। इसलिए केन्द्रीय मंत्रालयों और राज्य सरकारों से कहा गया है कि वे अपनी 1979-80 की वार्षिक आयोजना में उनके लिए एक विशेष हिस्सा रखें ताकि वे विभिन्न क्षेत्रों के कार्यक्रमों से पर्याप्त लाभ प्राप्त कर सकें। अनुसूचित जातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण सम्बन्धी कार्यक्रमों पर 1979-80 में 117 करोड़ रुपये का परिचय होगा।

45. 1979-80 की जनजातीय उप-आयोजना के लिए 70 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। इससे विभिन्न विकासशीलों के अन्तर्गत राज्य सरकारों से प्राप्त होने वाली धनराशियों की अनुपूर्ति के जागे। जनजातीय क्षेत्रों की कठिन परिस्थितियों में काम करने वाले राज्य सरकार के कर्मचारियों को प्रोत्साहन देने के लिए मातृ वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार राज्यों को अनुदान भी दिए जाएंगे।

46. ग्राम-उद्योगों का विकास केन्द्रीय आयोजना का एक महत्वपूर्ण अंग है। केन्द्रीय क्षेत्र में 1979-80 के लिए 193 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है जबकि चालू वर्ष में इसके लिए मूलतः 140 करोड़ रुपये रखे गए थे। राज्यों की आयोजनाओं में समुचित व्यवस्था करने और प्रोत्साहन शर्तों पर संस्थागत साधन उपलब्ध करा कर इस परिचय की अनुपूर्ति की जाएगी।

47. हाथकरघा उद्योग (हैंडलूम) हमारा अत्यन्त महत्वपूर्ण घास-उद्योग है। देश में लगभग 40 लाख हाथकरघे हैं जिनसे लगभग एक करोड़ लोगों को रोजगार मिल रहा है। उन्होंने 1978-79 में 250 करोड़ मीटर कपड़ा बनाया, और 1979-80 के लिए 2750 करोड़ मीटर का लक्ष्य रखा गया है। बुनकरों को सहकारी समितियों के रूप में संगठित करने के लिए इस क्षेत्र की सर्वोच्च सहकारी संस्थाओं को बहुरूप विपणन की सुविधा प्रदान करने के लिए और निर्यात के प्रयोजन से गहन विकास को बढ़ावा देने के लिए 1979-80 में 28 करोड़ रुपये की व्यवस्था की जा रही है।

48. ग्रामीण क्षेत्रों में डाक सेवाएं बढ़ाने की सरकार की नीति के अनुरूप 1979-80 में 5000 नए डाकघर खोलने और चलते-फिरते डाकघरों के जरिये 10000 डाक पट्टों (पोस्टल काउंटर) की व्यवस्था करने का प्रस्ताव है। 1979-80 में दूरसंचार पर 359 करोड़ रुपये का परिचय होगा और उसमें ग्रामीण क्षेत्रों में इन सुविधाओं के विस्तार पर पहले से ज्यादा जोर दिया जाएगा।

49. आधारभूत सुविधाओं के विकास के लिए पर्याप्त व्यवस्था करने पर भी ध्यान दिया गया है जिस पर कृषि और उद्योगों की प्रगति समान रूप से निर्भर करेगी। इस प्रकार बिजली, कोयला, उर्वरक और रसायन, खनिज, पेट्रोलियम, इस्पात और सड़कों तथा रेलों के लिए व्यवस्था को जो 1978-79 की केन्द्रीय आयोजना में 2733 करोड़ रुपये की थी, बढ़ाकर 1979-80 में 3122 करोड़ रुपये कर दिया गया है।

50. कृषि तथा उद्योग के विकास के लिए बिजली के उत्पादन को बढ़ाना भी बहुत जरूरी है। बिजली के क्षेत्र के लिए 1978-79 में 2217 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई थी जो पहले की तुलना में काफी ज्यादा थी। 1979-80 में विकास की गति को और भी तेज किया जाएगा और उसके लिए 2446 करोड़ रुपये के परिचय की व्यवस्था की जा रही है। बिजली के लिए आयोजनागत व्यवस्था का अधिकांश भाग राश्यों की आयोजनाओं में रखा जाएगा परन्तु केन्द्रीय क्षेत्र में बिजली की परियोजनाओं के लिए 382 करोड़ रुपये की राशि रखी गई है। 1979-80 में फरक्का में सुपर-थर्मल स्टेशन के रूप में एक बड़ी शुरुआत की जाएगी। उम्मीद है कि 1979-80 में 3000 मेगावाट बिजली के उत्पादन की अतिरिक्त क्षमता पैदा हो जाएगी, जब कि चालू वर्ष में 2500 मेगावाट की अतिरिक्त क्षमता के लिए व्यवस्था की गई थी। बिजली की वितरण की सुविधाओं में भी सुधार किया जा रहा है।

51. उर्वरकों के उत्पादन में आत्मनिर्भरता प्राप्त करना सरकार की नीति का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। उर्वरक संयंत्रों में निवेश के लिए 1979-80 की आयोजना में 254 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। इससे बहुत सी पहले से चल रही परियोजनाओं के खर्च का पूरा किया जाएगा जिनसे सरकारी क्षेत्र में उर्वरकों के उत्पादन को जो इस वर्ष 12 लाख मेट्रिक टन था, बढ़ाकर 1979-80 में 20 लाख मेट्रिक टन कर दिया जाएगा। पश्चिमी घाट पर गैस पर आधारित दो अणुतटीय संयंत्रों (ओफ गैस प्लांट्स) को और असम में एक और गैस पर आधारित संयंत्र का भी शुरू कर दिया जाएगा।

52. अर्थ-व्यवस्था में कार्यक्षमता बढ़ जाने से और अधिक पूंजी का निवेश किए जाने से चालू वर्ष के दौरान इस्पात की मांग में लगभग 15 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। छोटे इस्पात के संयंत्रों के उत्पादन में वृद्धि हो जाने से इस्पात की उस गंभीर कमी को जो अगस्त में हुई थी, टाल दिया गया है। इस्पात क्षेत्र के लिए 1979-80 में की जा रही 600 करोड़ रुपये की व्यवस्था की जा रही है। इस पर बड़ी हुई मांग के मन्दर्भ में विचार करना होगा। इस व्यवस्था से बाजारों और भिलाई के संयंत्रों का विस्तार किया जा सकेगा और मेलम में नए संयंत्र का काम आगे बढ़ाया जा सकेगा।

53. कोयला भी बिजली की तरह हमारे विकास की एक बुनियादी आवश्यकता है और इसके उत्पादन को बढ़ाया बहुत जरूरी है। अनुमान है कि चालू वर्ष में कोयले का उत्पादन 10.2 करोड़ मेट्रिक टन से ज्यादा नहीं होगा क्योंकि इसके उत्पादन पर गम्भीर बाढ़ों का प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। कोयला क्षेत्र की व्यवस्था को जो चालू वर्ष में 267 करोड़ रुपए की थी बढ़ाकर 1979-80 में 346 करोड़ रुपए किया जा रहा है।

54. तेल भी ऊर्जा (एनर्जी) का उतना ही महत्वपूर्ण स्रोत है और सरकार तेल क्षेत्रों का पता लगाने और उनका विकास करने के काम को बहुत महत्व दे रही है ताकि आयातित तेल पर हमारी निर्भरता कम से कम हो जाए। बंबई हाई के विकास का काम अगले साल बहुत दूर तक पूरा हो जाएगा। कोयली के तेल-शोधक कारखाने (रिफाइनरी) की क्षमता में 30 लाख मेट्रिक टन का विस्तार कर दिए जाने से देश की तेल-शोधन क्षमता प्रति वर्ष 3 करोड़ मेट्रिक टन तक पहुँच गई है। इस क्षेत्र के लिए 1979-80 में 622 करोड़ रुपए की व्यवस्था की जा रही है।

55. सड़कों भी राष्ट्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं और राष्ट्रीय राजपथों, सामरिक महत्व की सड़कों, उत्तर में सीमावर्ती क्षेत्रों की सड़कों और अन्तरराज्यीय आर्थिक महत्व की सड़कों के लिए 1979-80 में 120 करोड़ रुपए की व्यवस्था करने का प्रस्ताव है। राज्यों के राजपथों और जिला तथा ग्रामीण सड़कों के लिए राज्यों की आयोजनाओं में रखी गई धनराशियों से इस व्यवस्था की अनुपूर्ति की जाएगी।

56. हमारे देश में शहरीकरण की प्रक्रिया से गंदी और अनधिकृत बस्तियाँ बढ़ गई हैं। इन बस्तियों के निवासियों के लिए, जलपूर्ति, सामुदायिक शौचालय और स्नानागार, चौड़ी और पक्की गलियाँ तथा गलियों में रोजनी की व्यवस्था जैसी अत्यावश्यक सुविधाओं की भारी कमी है। इसलिए सरकार ने गंदी बस्तियों के मुद्धार की नीति का सक्रियता से पालन करने का निश्चय किया है। गंदी बस्तियों के मुद्धार के लिए 1974-78 में कुल मिलाकर 43 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे, उसके मुकाबले में 1978-83 की अवधि में 190 करोड़ रुपए के परियोजना की परिकल्पना की गई है। राज्यों को बड़े पैमाने पर इस कार्यक्रम को तत्परता से आगे बढ़ाना होगा। यदि वे इस प्रयोजन के लिए अपने यहां के शहरी क्षेत्रों के सम्पन्न वर्गों पर कर लगा कर अतिरिक्त साधन जुटाने का जिम्मा लेंगे तो सरकार को उनके प्रयत्नों की अनुपूर्ति करने में खुशी होगी। सरकार राज्यों से परामर्श करके इस बात की जाँच करेगी कि गंदी बस्तियों को मुद्धारने के कार्यक्रम को किस प्रकार तेजी से पूरा किया जा सकता है जिससे कि नगरों में रहने वाले गरीबों के रहन-सहन की बधाई में सुधार हो।

57. शिक्षा के क्षेत्र में प्राथमिकताओं के पुनर्निर्धारण में सरकार ने सार्वजनिक शिक्षा को सबसे अधिक महत्व दिया है। तदनुसार 1979-80 की केन्द्रीय आयोजना में प्रौढ़ शिक्षा की व्यवस्था को बढ़ाया जा रहा है और यह व्यवस्था अब केन्द्रीय आयोजना में शिक्षा के लिए निर्धारित 84 करोड़ रुपए के कुल परियोजना के लगभग 20 प्रतिशत के बराबर होगी।

58. अब यह व्यापक रूप से स्वीकार किया जाने लगा है कि कृषि और ग्राम-उद्योगों के विकास के कार्यक्रमों में तब तक पर्याप्त प्रगति नहीं होगी जब तक कि ग्रामीण जनता अपेक्षित कौशल प्राप्त नहीं कर लेगी तथापि, ग्रामीण युवकों को इन कौशलों का प्रशिक्षण प्रदान करने के कार्य में बहुत कम प्रगति हुई है। इसका एक कारण तो यह है कि ऐसे प्रशिक्षण के लिए किसी प्रभावोत्पादक कार्यक्रम की कमी है और दूसरे, कौशल को पूँजी के साथ जोड़ने वाले उचित संगठन का अभाव है। चूंकि यह प्रशिक्षण उत्पादन कार्यक्रम की सफलता के लिए एक अत्यावश्यक पूर्ववर्ती शर्त है इसलिए सरकार का प्रस्ताव है कि वर्ष के दौरान, ग्राम-नियोजन (सेल्फ-एम्प्लायमेंट) के लिए ग्रामीण युवकों के प्रशिक्षण के कार्यक्रम के तैयारी के लिए, उसके लिए वित्तीय व्यवस्था कर दी जाए।

59. यदि आर्थिक विकास के द्वारा अपने लोगों के जीवन स्तर में कोई ठोस सुधार करना है तो निस्संदेह जनसंख्या की वृद्धि की वर्तमान दर

पर नियंत्रण रखना होगा। बुधनियमन पिछले वर्षों में परिवार नियोजन के प्रति गत वृष्टिकोण अपनाए जाने के परिणामस्वरूप इस कार्यक्रम को भारी धक्का लगा है। हमारी कोशिश यह होनी चाहिए कि नए चालू किए गए परिवार कल्याण के कार्यक्रम को ठोस आधार पर रखें ताकि 33 प्रति हजार की वर्तमान जन्मदर को कम करके 1982-83 में 30 प्रति हजार की जन्मदर प्राप्त करने का राष्ट्रीय उद्देश्य पूरा किया जा सके। सामुदायिक स्वास्थ्य सेवक योजना, जो अक्टूबर 1977 में 741 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में शुरू की गई थी, ग्रामीण क्षेत्रों में प्रारंभिक चिकित्सा सुविधाओं का विस्तार करने की दिशा में जनता सरकार द्वारा उठाया गया एक नया उल्लेखनीय कदम था। देश के एक-तिहाई हिस्से को 1979-80 में और पूरे देश को 1982-83 तक इस योजना के अंतर्गत लाभ का प्रस्ताव है।

60. कार्य कुशलता के साथ-साथ मितव्ययता की जरूरत को ध्यान में रखते हुए आयोजना भिन्न व्यय को जहाँ तक वह बहुत जरूरी था वहाँ तक सीमित कर दिया गया है।

61. रक्षा व्यय के लिए 3050 करोड़ रुपए का अनुमान लगाया गया है जबकि चालू वर्ष में इसकी राशि 2845 करोड़ रुपए की थी।

62. खाद्य संबंधी आर्थिक सहायता (सब्सिडी) के लिए 560 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है जो चालू वर्ष की राशि से 10 करोड़ रुपए कम होगी। उर्वरकों के संबंध में भी जाने वाली आर्थिक सहायता के लिए अगले वर्ष में 448 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है जब कि चालू वर्ष में इसके लिए 319 करोड़ रुपए रखे गए थे।

63. ऋण परिशोधन प्रभारों के लिए 2161 करोड़ रुपए की राशि रखी जा रही है जो चालू वर्ष की राशि से लगभग 304 करोड़ रुपए ज्यादा होगी, यह वृद्धि प्रमुख रूप से आन्तरिक ऋणों के कारण होगी।

64. राज्यों को 232 करोड़ रुपए का सांविधिक अनुदान (स्टैंड-यूटरी ग्रान्ट) दिया जाएगा, इसकी तुलना में चालू वर्ष में इन अनुदानों की राशि 514 करोड़ रुपए की थी। अगले वर्ष की व्यवस्था सातवें वित्त आयोग की सिफारिश पर आधारित है। आयोग ने कुछ राज्यों को, उन की निबल ब्याज की देनदारी को पूरा करने के लिए और प्रशासन स्तर को ऊँचा उठाने के लिए, कुछ अतिरिक्त अनुदान दिए जाने की भी सिफारिश की है। मैंने इस समय इन प्रयोजनों के हेतु अनुदान देने के लिए कोई व्यवस्था नहीं की है और मैं पूरक धनराशि के लिए अनुरोध लेकर सदन के सम्मुख फिर उपस्थित होऊँगा जब कि संबंधित राज्य सरकारें प्रशासन के स्तर को ऊँचा उठाने की योजनाओं से संबंधित क्रियात्मक कार्यक्रम तैयार करके उनको अन्तिम रूप दे देगी और आयोग की सिफारिशों के अनुसार निबल ब्याज की देनदारियों का निर्धारण कर लिया जाएगा।

65. सरकार यह समझती है कि बढ़ते हुए सरकारी व्यय के कारण सम्मानित सभ्य भी उसकी तरह ही चिन्तित होंगे। इसलिए यह जरूरी है कि इस व्यय को बढ़ने से रोका जाए और यह सुनिश्चित किया जाए कि धनराशियों का उपयोग सामान्य हित को बढ़ावा देने के लिए कारगर हो सके कि या जाए। इसलिए सरकार ने उपयुक्त विचारणीय विषयों के साथ एक आयोग नियुक्त करने का फैसला किया है जो सरकारी व्यय की व्यापक रूप में जाँच करेगा। यह आयोग अन्य बातों के साथ साथ इस बात की भी जाँच करेगा कि वृद्धि की दर बढ़ाने में और गरीबों को कम करने में सरकारी व्यय का क्या योगदान रहा है। इस के अलावा आयोग गरीबों की समस्या को मुलजाने में सरकारी व्यय को अधिक प्रभावोत्पादक बनाने के लिए अर्थोपाय के संबंध में सुझाव देगा।

66. जहाँ तक प्राप्तियों का संबंध है, अनुमान है कि करों की मौजूदा दरों से 1979-80 में 10822 करोड़ रुपए का सकल कर-राजस्व

प्राप्त होगा और इस प्रकार चालू वर्ष के संशोधित अनुमान से 658 करोड़ रुपए अधिक प्राप्त होंगे। इस वृद्धि में संघ उत्पाद शुल्कों से 381 करोड़ रुपए और निगम तथा आय करों से 248 करोड़ रुपए मिलेंगे।

67. जैसा कि पहले कहा जा चुका है, सातवें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार अगले वित्तीय वर्ष से राज्यों को केन्द्रीय करों और शुल्कों में से पहले से काफी ज्यादा धन-राशि दी जाया करेगी। करों के मौजूदा स्तर पर अनुमान है कि अगले साल राज्यों का हिस्सा 3235 करोड़ रुपए का होगा जो कि चालू वर्ष में उनके हिस्से से 1278 करोड़ रुपए ज्यादा है। इसके परिणामस्वरूप केन्द्र का निवल (नेट) कर-राजस्व 7587 करोड़ रुपए का होगा जो कि चालू वर्ष की तुलना में 620 करोड़ रुपए कम है।

68. बाजार ऋणों से 1850 करोड़ रुपए प्राप्त होंगे जब कि चालू वर्ष में 1653 करोड़ रुपए प्राप्त हुए। अनुमान है कि वापसी प्रदायगी और व्याज की देनदारियों को पूरा करने के बाद निवल विदेशी सहायता 878 करोड़ रुपए की होगी जिसमें नए ऋणों के अन्तर्गत निकाली गई रकम भी शामिल है। अल्पवचन संग्रह से 650 करोड़ रुपए की प्राप्ति होगी। राज्यों द्वारा वापस भेजा किए गए ऋणों की राशि, जिसमें अधोप्राय अधिम शामिल नहीं है, 554 करोड़ रुपए की होगी जब कि चालू वर्ष में यह राशि 754 करोड़ रुपए की है। यह कमी सातवें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार ऋणशोधन कार्यक्रम के पुनर्निर्धारण के कारण हुई है।

69. 1979-80 के लिए केन्द्रीय सरकार को कुल प्राप्ति 16551 करोड़ रुपए की होगी। आने वाले वर्ष के लिए कुल व्यय 18526 करोड़ रुपए का होगा। इस प्रकार करों की वर्तमान दरों के अनुसार बजट में कुल मिलाकर 1975 करोड़ रुपए का घाटा रहेगा।

भाग-ख

70. अब मैं अपने सफेद कर-प्रस्तावों पर आता हूँ।

71. जाहिर है कि इतना बड़ा घाटा एक बड़े कर प्रयत्न के बिना पूरा नहीं किया जा सकता। किन्तु, मेरे इन कर-प्रस्तावों का लक्ष्य आवश्यक साधन जुटाने के अलावा उन तीन उद्देश्य को भी पूरा करना है जो, मैं समझता हूँ, इस सदन में हर व्यक्ति को स्वीकार्य होंगे। ऐसे देश में जहाँ अधिकांश जनता गरीबी की रेखा (पावर्टी लाइन) से नीचे का जीवन व्यतीत कर रही हो, आय की इन विषमताओं को घटाकर कम से कम कर देना होगा। इन विषमताओं के कारण विलासितापूर्ण उपभोग होता है जिससे बचन की प्रवृत्ति और परिश्रम करने की इच्छा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इसलिए कर नीति ऐसी होनी चाहिए जिससे ये विषमताएँ कम हों।

72. मेरे कर प्रस्तावों का दूसरा उद्देश्य उत्पादन को बढ़ाना और अपव्यय को रोकना है। गरीबी को मिटाने के लिये सर्वप्रथम उत्पादन को बढ़ाने की जरूरत होगी। चूंकि साधनों की बहुत कमी है इसलिए कर नीति के जरिये साधनों का व्यर्थ और अनुत्पादक कार्यों की और से हटाकर उत्पादक प्रयोजनों के लिए रखा जाना चाहिए। इसके द्वारा ऐसी वस्तुओं के उपभोग (कंजम्पशन) को भी निरस्त/हटा दिया जाना चाहिए जो निच्य हों लोगों के स्वास्थ्य को हानि पहुँचाते हैं।

73. इन कर-प्रस्तावों का तीसरा उद्देश्य यह है कि कृषि उत्पादन को बढ़ावा देकर और उत्पादन की श्रम प्रधान तकनीकों को प्रोत्साहन देकर तथा बड़े उद्योगों के संबंध में लघु और कुटीर उद्योगों की प्रतियोगी क्षमता बढ़ाकर बेरोजगारी और कम-रोजगारी को खरम किया जाए।

74. सबसे पहले मैं प्रत्यक्ष करों को लेता हूँ।

75. मैं सभी श्रेणियों के निगम-भिन्न करदाताओं के मामले में आय-कर पर संघ के प्रयोजनों के लिए लगने वाले अधिभार (सरचार्ज) की दर को 15 प्रतिशत से बढ़ाकर 20 प्रतिशत करने का प्रस्ताव करता हूँ। इस प्रस्ताव का अमर यह होगा कि वैयक्तिक आय-कर की सीमांतिक दर जो इस समय 69 प्रतिशत है, बढ़ाकर 72 प्रतिशत हो जाएगी। इस

उपाय से एक वर्ष में 46 करोड़ रुपए का अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होगा। किन्तु 1979-80 में इससे केवल 37 करोड़ रुपए की प्राप्ति होगी। यह एक छोटा सा त्याग है जिसे अपने गरीब भाइयों के हित में करने के लिए मैं उन 35 लाख करदाताओं को कह रहा हूँ जो हमारी कुल जनसंख्या का बहुत छोटा भाग हैं और जो देश की आय का बहुत बड़ा भाग प्राप्त करने हैं।

76. मैं जानता हूँ कि राज्य सरकारें संघ के प्रयोजनों के लिए अधिभार लगाए जाने के विरुद्ध हैं क्योंकि अधिभार से मिलने वाले राजस्व में राज्यों को कोई हिस्सा नहीं मिलता लेकिन मैं अपने दूसरे कर-प्रस्तावों में इस बात का ध्यान रखा है कि केन्द्र के अतिरिक्त कर-प्रयत्न से होने वाली प्राप्ति में राज्यों को भी उचित हिस्सा मिले।

77. वित्त अधिनियम, 1978 में दी गई दर अनुसूची के अन्तर्गत जिन मामलों में कराधान योग्य आय, छूट की सीमा से मामूली सी अधिक हो, वहाँ 10,000 रुपए से ऊपर की आय पर कर की देनदारी 70 प्रतिशत तक सीमित की गई है। यह व्यवस्था कई मामलों में कुछ कड़ी पड़ती है। सीमांतिक मामलों में कुछ नरमी बरतने के लिए मैं ऐसे मामलों में देय कर को 10,000 रुपए से ऊपर की राशि पर 30 प्रतिशत तक सीमित करने का प्रस्ताव करता हूँ। इसका लाभ उन लोगों को मिलेगा जिनकी आय 12,000 रुपए तक है।

78. साधनों की नितान्त आवश्यकता को देखते हुए, मैं आयकर दाताओं के लिए अनिवार्य निक्षेप योजना को और दो साल के लिए चालू रखने का प्रस्ताव करता हूँ। इससे वित्तीय वर्ष 1979-80 में 170 करोड़ रुपए के अतिरिक्त साधन पैदा होंगे।

79. धन की असमानताओं का तो आय की असमानताओं से भी औचित्य है। इसलिए मैं निवल धन के उच्च खंडों (स्लेब) पर धन-कर की दरों को बढ़ाने का प्रस्ताव करता हूँ। अब यह दर 10 लाख रुपए रुपए और 15 लाख रुपए के बीच के निवल धन पर 2.5 प्रतिशत की वर्तमान दर के स्थान पर 3 प्रतिशत होगी और 15 लाख रुपए से ऊपर के निवल धन पर 3.5 प्रतिशत की वर्तमान दर के स्थान पर 5 प्रतिशत होगी। 10 लाख रुपए तक के खंडों पर धन-कर की दरों में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। जिन हिन्डू अधिभक्त कुटुम्बों में छूट की सीमा से ऊपर स्वतंत्र रूप से निवल धन रखने वाले एक या अधिक सदस्य हो उन पर लगने वाली दरों में तबतक परिवर्तन कर दिया जाएगा। इन परिवर्तनों से एक वर्ष में 6.6 करोड़ रुपए का अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होगा। किन्तु धन-कर की नई दरें निर्धारण वर्ष 1980-81 से ही लागू होगी इसलिए 1979-80 में इससे कोई अतिरिक्त राजस्व नहीं मिलेगा।

80. यह तो मानना ही होगा कि सिर्फ प्रत्यक्ष करों की दरों में परिवर्तन कर देने से ही हम आय और धन की विषमताओं को सही स्तर तक नहीं घटा सकते। जैसा कि सदन को मालूम है, कर-अपवर्धन (टैक्स इन्वेजन), जोकि काला धन पैदा होने का मूल कारण है, प्रत्यक्ष-करों के प्रगामी स्वरूप को बहुत अधिक प्रभावित करता है। काला धन एक ऐसा भुन है जो कि अनुसूची अर्थव्यवस्था को काट रहा है। यह जरूरी है कि हमारे कर सम्बन्धी कानूनों पर कारगर ढंग से प्रमल करके इस बुराई का सामना किया जाए। मैं सदन को यह आश्वासन देना चाहूंगा कि मैं अत्यन्त उत्साह और शक्ति के साथ अपने आपको इस काम में लगा दूंगा।

81. भूक में वैयक्तिक आयों पर साध-कर के अधिभार को बढ़ा रहा हूँ इसलिए मैं सोचता हूँ कि निगमित क्षेत्र को भी राजकोष में कुछ और ज्यादा अंशदान देना चाहिए। तदनुसार मैं प्रस्ताव करता हूँ कि कम्पनियों के मामले में आयकर सम्बन्धी अधिकार को 5 प्रतिशत से बढ़ाकर 7.5 प्रतिशत कर दिया जाए। इससे उन पर भारी बोझ नहीं

पड़ेगा, क्योंकि निगमों पर लगने वाले कर की प्रभावी दर निश्चित बरों से कम है। इन उपायों के अन्तर्गत 35 करोड़ रुपये के अतिरिक्त राजस्व की प्राप्ति होगी। किन्तु 1979-80 के दौरान केवल 28 करोड़ रुपये ही प्राप्त होंगे।

82. पूंजी-अभिलाषों (केपिटल गेन्स) के काराधान की योजना का 1977 में कई एक दिशाओं में संशोधित किया गया था। एक परिवर्तन तो यह था कि यदि परिसम्पत्ति किसी से प्राप्त रकम को, उसके छः महीने के अन्तर-अन्तर कुछ विनिश्चित परिसम्पत्तियों में फिर से लगा दिया जाए तो ऐसे मामले में वीर्याधिक पूंजी-अभिलाष पर लगने वाले आय-कर से छूट मिलेगी। चूंकि परिसम्पत्ति के मालिकों को अधिकतर ये पूंजी-अभिलाष कोई प्रयास किए बिना प्राप्त होते हैं इसलिए इस छूट से आय का उपार्जन करने वाले लोगों के मुकाबले, परिसम्पत्तियों के मालिकों को अनुचित लाभ प्राप्त होना है, और इस प्रकार उनसे समाज में विषमताएं बढ़ती हैं। इसलिए मैं, 28 फरवरी, 1979 के बाद किए जाने वाले अन्तरणों के सम्बन्ध में, पूंजी-अभिलाष सम्बन्धी इस छूट को समाप्त करने का प्रस्ताव करता हूं। इस उपाय से प्रति वर्ष 14 करोड़ रुपये अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होगा। चूंकि पूंजी-अभिलाषों के सम्बन्ध में पेशगी कर की अदायगी नहीं की जाती, इसलिए 1979-80 में इससे राजस्व की कोई वृद्धि नहीं होगी।

83. जीवन बीमा प्रीमियमों, भविष्य निधि अंशदानों तथा बचत करने के अन्य अनुमोदित रूपों में जो वीर्याधिक बचतें की जाती हैं, वे हासिक कुछ वांछनीय सामाजिक और आर्थिक उद्देश्यों को पूरा करती हैं फिर भी उनके सम्बन्ध में मिलने वाली मौजूदा रियायतों से उच्चतर आय-वर्गों के करदाताओं को ही अपेक्षाकृत अधिक अनुदान में लाभ मिलता है। इस समय, अर्हताप्राप्त बचत के पहले 5000 रुपये पर 100 प्रतिशत, उससे अगले 5000 रुपये पर 50 प्रतिशत तथा शेष पर 40 प्रतिशत की कटौती की जा सकती है। किन्तु मेरे प्रस्ताव के अनुसार जबकि अर्हताप्राप्त बचतों के पहले 5000 रुपये पर 100 प्रतिशत कटौती का हक कायम रहेगा, तथापि अगले 5000 रुपये की ऐसी बचतों पर अर्हता प्राप्त कटौती को घटाकर 35 प्रतिशत कर दिया जाएगा और बचत की शेष राशि के सम्बन्ध में इसे 20 प्रतिशत कर दिया जाएगा। इस उपाय से भी प्रतिवर्ष 9.6 करोड़ रुपये की आमदनी होगी। किन्तु वित्तीय वर्ष 1979-80 में 7.6 करोड़ रुपये की प्राप्ति होगी।

84. मेरा प्रस्ताव है कि रजिस्टर्ड फर्मों के द्वारा पेशगी कर की अदायगी की आरम्भिक सीमा को 30,000 रुपये से कम करके 20,000 रुपये कर दिया जाए। 1979-80 में इस उपाय से 12 करोड़ रुपये के अतिरिक्त राजस्व की प्राप्ति होगी।

85. देश में बढ़े पैमाने पर विद्यमान बेरोजगारी इस बात की अपेक्षा करती है कि पूंजी-प्रधान तकनीकों की बजाए हमें श्रम-प्रधान तकनीकों को ही बढ़ावा देना चाहिए। यद्यपि यह सच है कि कुछ एक उद्योग-धन्धों में तकनीकों के चुनाव का क्षेत्र सीमित होता है, फिर भी जहां कहीं व्यवहार्य हो हमें श्रम-प्रधान उत्पादन प्रणाली को ही सबसे अधिक पसन्द करना चाहिए। हमारे राजकोषीय कानून तथा कर-सम्बन्धी रियायतें खास तौर पर ऐसी होती चाहिए जिनसे उत्पादन की ऐसी तकनीकों को बढ़ावा मिले, जिनसे रोजगार के ज्यादा अवसर पैदा हों।

86. इसलिए, मैं अर्थशास्त्रियों तथा कर-प्रशासकों की एक विशेषज्ञ समिति नियुक्त करने का प्रस्ताव करता हूं जो हमारे कर सम्बन्धी कानूनों में, खासकर निगम कर और केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क से सम्बन्धित कानूनों में की गई रियायतों के, उद्योग में इस्तेमाल की जाने वाली उत्पादन की तकनीकों पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन करेगी और ऐसी सिफारिशें करेगी जिनसे उत्पादन के श्रम-प्रधान तरीकों को अपनाने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा। समिति के गठन और उसके

विचारणीय विषय भी इसी तय कर दिए जाएंगे और समिति से कहा जाएगा कि वह अपनी रिपोर्ट कम से कम समय में प्रस्तुत कर दे।

87. पूंजी नियोजन के सम्बन्ध में दी जाने वाली कर सम्बन्धी रियायतों में से एक रियायत है आयकर अधिनियम में कर की छूट की व्यवस्था। इस समय यह रियायत, उन सभी औद्योगिक उपकरणों के सम्बन्ध में उपलब्ध है जो पहली अप्रैल 1981 से पहले उत्पादन करना शुरू करें। मैं उन औद्योगिक उपकरणों के मामले में इस रियायत को वापस लेने का प्रस्ताव करता हूं जो आयकर अधिनियम की ग्यारहवीं अनुसूची में दिए गए गैर-आयमिकता प्राप्त उद्योगों में लगे हुए हैं और जो 31 मार्च 1979 के बाद उत्पादन का काम शुरू करेंगे।

88. अभी हाल के वर्षों में वाणिज्यिक बैंकों, खासकर सरकारी क्षेत्र के बैंकों से कहा गया था कि वे ग्रामीण क्षेत्रों में जाएं और वहां अपने ऋण-कार्यक्रम का विस्तार करें। देहाती ह्वाकों में बैंकिंग कार्य को बढ़ावा देने तथा देहाती अधिमों (रूरल एक्वाज) के सम्बन्ध में जोखिम उठाने के लिए अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा अपनी वर्तमान आमदनी में से पर्याप्त धन की व्यवस्था करने के उद्देश्य से उन्हें सहायता पहुंचाने के लिए मैं आयकर अधिनियम में यह संशोधन करने का प्रस्ताव करता हूं कि अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक की ग्रामीण शाखाओं द्वारा दिए गए अधिमों के सम्बन्ध में इस अनुसूचित बैंकों द्वारा अशोध्य तथा संविध्य ऋणों के लिए की जाने वाली व्यवस्था की राशि के सम्बन्ध में कटौती की मंजूरी दी जाए। पर इस प्रकार की कटौती ग्रामीण शाखाओं द्वारा दिए गए कुल शीतत अधिमों के 1.5 प्रतिशत तक सीमित होगी। इस संशोधन से 1979-80 में 12 करोड़ रुपये के राजस्व की हानि होगी, पर यह हानि एक अच्छे काम के लिए होगी।

89. मैं कृषि पुनर्वित्त और विकास निगम को जो छूट देना चाहता हूं उसका जिक्र मैं पहले कर चुका हूं। यह छूट उनी छट के अनुरूप है जो भारतीय औद्योगिक विकास बैंक को पहले से ही मिल रही है। इस निर्णय से प्रति वर्ष 5 करोड़ रुपये के राजस्व का नुकसान होगा। अनुमान है कि 1979-80 में यह नुकसान 10 करोड़ रुपये का होगा क्योंकि 1978-79 में अदा किए गए अधिम करों को भी वापस करना होगा।

90. इस समय कर-योग्य लाभों का हिसाब लगाते हुए कम्पनियों और सहकारी समितियों द्वारा ग्रामीण विकास के अनुमोदित कार्यक्रमों पर किए गए खर्च की कटौती कर दी जाती है। इस प्रयोजन के लिए, कार्यक्रम को एक "विहित प्राधिकरण" से अनुमोदित कराना पड़ता है जो कि एक अन्तर-मन्त्रालयिक समिति है और जिसका अध्यक्ष कृषि और सिंचाई मन्त्रालय का सचिव है। कम्पनियों तथा सहकारी समितियों ने ग्रामीण विकास कार्यक्रम में काफी विलचस्पी दिखाई है। ग्रामीण विकास की इस तरह की योजनाओं को शीघ्र मंजूरी देने के लिए मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि अब से इन योजनाओं को राज्य स्तर पर ही एक ऐसी समिति द्वारा अनुमोदित किया जाए जिसमें आय-कर अनुसूचित तथा राज्य सरकार द्वारा मनोनीत उसका एक वरिष्ठ अधिकारी हो।

91. मैं यह भी प्रस्ताव करता हूं कि ग्रामीण विकास कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए व्यक्तियों को आवश्यक प्रशिक्षण देने के कार्य में लगी हुई अनुमोदित संस्थाओं को आयकरदाताओं द्वारा दिए गए दानों को आयकर से मुक्त कर दिया जाए।

92. इस समय, कारबार और वृत्ति (प्रोफेशन) में लगे हुए आयकरदाता ही ग्रामीण विकास के कार्यक्रमों में लगी हुई अनुमोदित संस्थाओं को दिए गए दानों के संबंध में 100 प्रतिशत की कटौती का लाभ पाने के हकदार हैं। मैं इस रियायत को अन्य श्रेणियों के आयकरदाताओं पर भी लागू करने का प्रस्ताव करता हूं, इस तरह की रियायत वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए अनुमोदित वैज्ञानिक अनुसंधान संगठनों, विश्वविद्यालयों, कांसेजों और अन्य संस्थाओं को दिए गए दानों पर भी दी जाया करेगी।

93. एक ऐसी व्यवस्था करने का प्रस्ताव भी किया जाता है जिसके अन्तर्गत संघीय द्रुत सहायक समितियों के कर-योग्य लाभों का हिसाब लगाते समय इनमें संबंधित प्राथमिक सहायक समितियों के सदस्यों के पशुओं की बीमा के लिए उन संघीय समितियों द्वारा भुगतान की गई किस्तों की कटौती करने की अनुमति दी जाएगी।

94. खुम्बी (मणारूम) की खेती करने के लिए प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से मैं यह प्रस्ताव करता हूँ कि नियंत्रित परिस्थितियों के अन्तर्गत खुम्बी उगाने के कारखानों से होने वाली आय की एक-तिहाई राशि अथवा 10,000 रुपये की राशि को हमसे से जो भी अधिक हो, आयकर से मुक्त किया जाए।

95. जैसा कि सम्मानित सदस्यों को मालूम है, वित्त (संख्या 2) अधिनियम, 1977 के अन्तर्गत खादी और ग्रामोद्योग आयोग को आय-कर से मुक्त किया गया है। अब यह प्रस्ताव किया जाता है कि राज्य अधिनियमों के अन्तर्गत स्थापित किए गए राज्य खादी और ग्रामोद्योग बोर्डों की आय को आयकर से मुक्त किया जाए।

96. उपभोक्ता सहायक समितियाँ उपभोक्ताओं को उचित कीमतों पर सामान उपलब्ध कराने का प्रशासनीय काम करती रही हैं। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के संबंध में, जिसका आगे विकास होना है, अपनी उचित भूमिका अदा करने के लिए हम तरह की समितियों के विकास का प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से मैं यह प्रस्ताव करता हूँ कि इस प्रकार की समितियों के मामले में मौजूदा कर-मुक्त लाभों के स्तर को 20,000 रुपये से बढ़ा कर 40,000 रुपये कर दिया जाए।

97. निर्यात बाजार विकास छूट के सम्बन्ध में आयकर अधिनियम की धारा 35(ख) के दायरे को पिछले वर्ष सीमित कर दिया गया था। मैंने पहले इस बात का जिक्र किया था कि चारों वर्षों में निर्यात में गिरावट आई है और उसमें वृद्धि करने की आवश्यकता है। अतः एक दीर्घावधि आधार पर निर्यात बाजार का विकास करने के लिए निर्यातकर्ताओं को सक्षम बनाने के उद्देश्य से निर्यात बाजार विकास छूट के दायरे को बढ़ाने का प्रस्ताव है। आयकर अधिनियम की धारा 35(ख) के अन्तर्गत अब सभी निर्यातकर्ताओं को अर्हताप्राप्त व्यय पर 133.3 प्रतिशत की समान दर पर भारित कटौती की सुविधा उपलब्ध होगी। इस प्रयोजन के लिए आयकरदाता द्वारा अपने कारखानों के संचालन के दौरान भारत के बाहर अपनी वस्तुओं, सेवाओं अथवा सुविधाओं के बारे में विज्ञापन अथवा प्रचार पर किए गए खर्च को अर्हताप्राप्त व्यय में शामिल किया जाएगा। इस रियायत के परिणामस्वरूप प्रति वर्ष लगभग 8 करोड़ रुपये के राजस्व का नुकसान होगा। परन्तु, 1979-80 में यह नुकसान 4 करोड़ रुपये का होगा।

98. हिन्दी में तथा अन्य भारतीय भाषाओं में विश्वविद्यालय स्तर की पाठ्य पुस्तकों के लेखन को प्रोत्साहन देने के लिए मैं यह प्रस्ताव करता हूँ कि इस प्रकार के पुस्तक लेखकों को, इस संबंध में होने वाली आय के 25 प्रतिशत के बराबर की कटौती किए जाने की अनुमति दी जाए। इन भाषाओं में शब्दकोश और विश्वकोश तैयार करने वाले लेखकों को भी अपनी कर-योग्य आय का हिसाब लगाने के प्रयोजन के लिए इस प्रकार की कटौती का लाभ मिलेगा। यह रियायत कर-निर्धारण वर्ष 1980-81 के लिए तथा उसके बाद के चार वर्षों के लिए उपलब्ध होगी।

99. एक और जहाँ मैं कर-अपवर्जन (टैक्स इक्वेशन) के विज्ञापन तेज करना चाहता हूँ, वहाँ दूसरी ओर मैं यह भी चाहूंगा कि आयकर के मामलों को पहले की अपेक्षा अधिक तत्परता के साथ निपटाया जाए। हम समय, यदि आयकर आयुक्त किसी आवेदन-पत्र के संबंध में रुतिय मुद्दों पर कोई आपत्ति उठाते हैं तो आयकर-परिनिर्धारण-आयोग (इकम टैक्स सेजलनेट कमीशन) को ऐसे मामलों में कोई कार्यवाई करने

की मनाही है। प्रत्यक्ष-कर-विधि समिति ने यह सिफारिश की है कि परिनिर्धारण के आवेदन-पत्र को तभी नामंजूर किया जाए जबकि आयोग इस बात में संतुष्ट हो जाए कि आयुक्त ने उपयुक्त तथा विधिमानी कारणों के आधार पर आपत्ति उठाई है। इस सिफारिश को इन शर्तों के साथ कार्यान्वित करने का प्रस्ताव रखा जाता है कि आयकर आयुक्त द्वारा उठाई गई आपत्ति को रद्द करने से पहले परिनिर्धारण आयोग को उसकी सुनवाई कर लेनी चाहिए।

100. प्रत्यक्ष-कर-विधि-समिति ने आय-कर अधिनियम और धन-कर अधिनियम में कुछ संशोधन करने का प्रस्ताव किया है जिसका उद्देश्य आय और धन के परिवार के भीतर अन्तरणों के जरिये करों से बचने की प्रक्रिया पर रोकथाम से संबंधित उपबन्धों में विद्यमान कृत्रिमों को दूर करना है। मैंने उसकी सिफारिशें मान ली हैं और उन्हें वित्त विधेयक के जरिये कार्यान्वित किया है।

101. जैसा कि मैंने हमसे पहले बताया है, मेरे प्रस्तावों का दूसरा उद्देश्य समाज के सम्पन्न लोगों के रहन-सहन की शैली पर रोक लगाना है जिससे कि उसका प्रवर्णनात्मक असर बचन और निवेश पर प्रतिकूल प्रभाव न डाले। इस सम्बन्ध में लक्जरी होटलों में आवास तथा मनोरंजन के लिए जो भत्ता-प्रनाप खर्च किया जाता है उस पर गंभीरता से विचार करना जरूरी है। इन लक्जरी होटलों में इस तरह के प्रवर्णनात्मक उपभोग को रोकने के उद्देश्य से होटलों की सकल पातियों पर एक नया कर लगाने का प्रस्ताव रखा जाता है। चूंकि मेरा इरादा यह है कि राज्य, होटलों में प्रतिथियों को परसो जाने वाली खाद्य वस्तुओं और पेय पदार्थों पर अब तक जो बिक्री कर लगाते रहे हैं उसे जारी रखें, लेकिन इन वस्तुओं की बिक्री से प्राप्त होने वाली रकम को कर आधार (टैक्स बेस) में शामिल नहीं किया जाएगा। इस नए उपाय के बारे में ब्योरे तैयार किए जा रहे हैं और इस संबंध में आवश्यक कानून शीघ्र ही संसद में पेश किया जाएगा।

102. वित्त-विधेयक के माध्यम से आयकर विधि में जो अन्य संशोधन किए जा रहे हैं उनका कोई ज्यादा महत्व नहीं है और अधिकोश संशोधन वर्तमान उपायों के व्यापककरण के लिए तथा उनको युक्तिसंगत बनाने के लिए हैं।

103. कर संबंधी इन सभी उपायों से पूरे वर्ष में कुल मिलाकर 101.2 करोड़ रुपये के अनिश्चित राजस्व प्राप्त होंगे और 1979-80 में इन से 58.6 करोड़ रुपये की प्राप्ति होगी। 1979-80 में इसमें से लगभग 12 करोड़ रुपये राज्यों को उनके हिस्से के रूप में मिलेंगे। इनके अतिरिक्त आयकरदाताओं के लिए अनिवार्य निक्षेप योजना को जारी रखने से 1979-80 में 160 करोड़ रुपये के अनिश्चित साधन प्राप्त होंगे।

104. अब मैं अत्यंत करों की ओर आता हूँ।

105. मैं सर्वप्रथम उन महत्वपूर्ण राहों का उल्लेख करना चाहूंगा जो मैं उत्पाद-शुल्कों (एक्साइज ड्यूटी) में देने का प्रस्ताव करता हूँ। सभी रासायनिक उर्वरकों पर केन्द्रीय उत्पाद-शुल्कों की वर्तमान दरों में 50 प्रतिशत की कमी कर दी जाएगी। इसका अर्थ यह होगा कि यूरिया पर, जो सबसे अधिक महत्वपूर्ण रासायनिक उर्वरक है, बुनियादी केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क मूल्यानुसार 15 प्रतिशत से घट कर 7.5 प्रतिशत, और इकहरे (मिगल) तथा निहरे सुपर फास्फेट उर्वरक पर मूल्यानुसार 7.5 प्रतिशत से घट कर 3.75 प्रतिशत हो जायेगा। यह कमी आयोजित उर्वरकों पर लगाए जाने वाले प्रतिसत्तुलनकारी शुल्कों में भी तदनुसृत प्रतिबिम्बित होगी। इस परिवर्तन के फलस्वरूप यूरिया की कीमत में प्रति मैट्रिक टन लगभग 100 रुपये की कमी करना संभव होगा। उत्पाद शुल्क में अब घोषित की गई राहत के संदर्भ में अन्य किसी के उर्वरकों की कीमतों भी अपेक्षाकृत कम हो जाएंगी। इस निर्णय के कारण केन्द्रीय उत्पाद-शुल्कों के अन्तर्गत 75.6 करोड़ रुपये तथा सीमा-शुल्कों के अन्तर्गत 30 करोड़ रुपये के राजस्व का बलिदान करना पड़ेगा।

106. हालांकि, देहली इलाकों में बिजली लगाने के काम का विस्तार होने से बिजली में चलने वाले पम्पसेटों की संख्या बड़ी तेजी से बढ़ रही है फिर भी हमारे देश के अधिकतर भागों में किसानों को बिजली से चलने वाले पम्पसेटों का इस्तेमाल करना पड़ता है। इस बड़े वर्ग को राहत देने के एक उपाय के रूप में इसके डीजल तेल पर 155.72 रुपये प्रति किलोमीटर की दर से लगने वाले मौजूदा उत्पाद-शुल्क के स्तर को कम कर के 75 रुपये प्रति किलोमीटर करने का प्रस्ताव रखा गया है। सरकार को मालूम है कि इस तेल का केवल 45 प्रतिशत भाग ही कृषि क्षेत्र में इस्तेमाल में लाया जाता है। चूंकि इस तेल के अंतिम उपयोग (पंज यूज) पर नियंत्रण रखना कठिन है और चूंकि इसके शेष भाग में से भी काफी अधिक मात्रा का उपयोग बिजली पैदा करने के लिए तथा लघु उद्योगों के द्वारा किया जाता है इसलिए उत्पाद-शुल्क में की गई इस कमी का लाभ, बिना भेदभाव के, सभी उपभोक्ताओं तक पहुंचाने का प्रस्ताव किया जाता है। इस रियायत के परिणामस्वरूप राजकोष को प्रतिवर्ष 12.40 करोड़ रुपये के राजस्व की हानि होगी।

107. राज्य कृषि उद्योग निगमों तथा केन्द्रीय सरकार द्वारा आयोजित पावर टिलरों को भी पूरी तरह सीमा-शुल्कों से मुक्त करने का प्रस्ताव रखा जाता है। क्योंकि इन उपकरणों से छोटी ज़ोनों में खेती की पैदावार बढ़ाने में सहायता मिलेगी। सम्मानित सदस्यों को मालूम होगा कि देश में बनने वाले पावर टिलर तो पहले से ही केन्द्रीय उत्पाद-शुल्कों से मुक्त हैं।

108. पी० बी० सी० रेजिनो से बनी पाइपों से पानी से जानें से खेतों में पानी की रिसाई (सीपेज) और बरबादी कम हो सकती है और इसके फलस्वरूप सिंचाई की प्रभावोत्पादकता बढ़ सकती है। चूंकि सिंचाई के लिए पी० बी० सी० पाइपों का निर्माण करने के लिए मैं इस कच्ची सामग्री को सस्ते दामों पर उपलब्ध कराना चाहता हूँ और इसके साथ ही यह भी चाहता हूँ कि इस रियायत का अन्य प्रयोजनों के लिए बुरा उपयोग न किया जाए, इसलिए यह प्रस्ताव किया जाता है कि आजमाइशों और पर, इस प्रयोजन के लिए आयोजित पी० बी० सी० रेजिनो को उस समय से सीमा-शुल्कों से मुक्त कर दिया जाए जब कि एक ऐसी योजना की कार्यपद्धतियाँ तैयार हो जाएँ जिससे उपर्युक्त दोनों उद्देश्यों की पूर्ति हो।

109. मैं औषधियों (ड्रग) और दवाइयों (मेडिसिन) के क्षेत्र में दी जा रही राहत का भी जिक्र करूँगा। जीवन रक्षा करने वाली औषधियों के निर्माण के लिए आवश्यक 22 बिनिचिष्ट थोक औषधियों को पूर्णतः सीमा शुल्कों से मुक्त करने और 17 मध्यवर्ती बिनिचिष्ट थोक औषधियों पर मूलानुसार 75 प्रतिशत सीमाशुल्क को कम करके 25 प्रतिशत मूलानुसार करने का प्रस्ताव रखा जाता है। उत्पाद-शुल्क के क्षेत्र में, पेटेंट अधिनियम के तहत दवाइयों को, जिनमें जीवित रखा करने वाली औषधियाँ शामिल हैं, विशेष उत्पाद-शुल्क से मुक्त करने का प्रस्ताव किया जाता है। कुल मिला कर इन उपायों के परिणामस्वरूप अनुमानतः प्रति वर्ष 7.04 करोड़ रुपये के राजस्व का नुकसान होगा।

110. अब मैं दूरगामी प्रभाव डालने वाले एक प्रस्ताव की ओर आता हूँ। इसका संबंध अनिमित तम्बाकू से है जिस पर 1943 से उत्पाद-शुल्क लगता आ रहा है। इस शुल्क के कारण उत्पाद-शुल्क तन्त्र बहुसंख्यक तम्बाकू उत्पादकों और लाइसेंसधारियों के सम्पर्क में आता है। तम्बाकू को सभी प्रकार के उत्पाद-शुल्कों से जिनमें अतिरिक्त उत्पाद-शुल्क भी शामिल हैं, पूरी तरह मुक्त करने और इस प्रकार एक ही बार में लगभग दस लाख तम्बाकू उत्पादकों, संसाधकों, (क्यूरर), छोटे व्यापारियों और गोदाम लाइसेंसधारियों को उत्पाद-शुल्क के नियंत्रण से मुक्त करने का प्रस्ताव किया जाता है। मुझे इसमें कोई सन्देह नहीं कि इस दुखदायी शुल्क को जो कि औपनिवेशिक काल की विरासत के रूप में बला आ रहा है, समाप्त करने के निर्णय का हमारे देश के तम्बाकू उगाने वाले इलाकों के किसानों द्वारा व्यापक रूप से स्वागत किया जाएगा। इस

रियायत से 121.20 करोड़ रुपये के राजस्व की हानि होगी। परन्तु, मैं इसमें से 115.71 करोड़ रुपये की हानि को, निमित्त तम्बाकू के उत्पादों पर समुचित रूप से शुल्क दरों को बढ़ा कर पूरा करने का प्रस्ताव करता हूँ।

111. मैं सिगरेटों पर भी बाद में हाथ उठाऊँगा। इस समय मैं निमित्त तम्बाकू के अन्य उत्पादों की चर्चा करूँगा। जहाँ तक शॉड वाली बीड़ियों का संबंध है, तम्बाकू के स्तर पर मौजूदा शुल्क, बीड़ी पर लगने वाले शुल्क के साथ मिल कर, प्रति हजार बीड़ियों पर लगभग 3 रुपये बैठता है, शॉड वाली प्रति हजार बीड़ियों पर 3.60 रुपये की समेकित दर निश्चित करने का प्रस्ताव किया जाता है। शॉड वाली तथा बिना शॉड वाली दोनों किस्मों के बीड़ी निर्माताओं द्वारा निमित्त बिना शॉड वाली बीड़ियों पर उसी दर पर शुल्क लगेगा। इस समय, बिना शॉड वाली बीड़ियों की शुल्क से मुक्त है लेकिन उन पर तम्बाकू के स्तर पर शुल्क लगता है जो प्रति हजार बीड़ियों पर लगभग नब्बे पैसे बैठता है। बिना शॉड वाली अन्य बीड़ियों पर प्रति हजार 1.60 रुपये की दर से एक नाममात्र का समेकित शुल्क लगाने का प्रस्ताव किया जाता है। परन्तु, केवल बिना शॉड वाली बीड़ियों के छोटे निर्माताओं को राहत देने के उद्देश्य से उन निर्माताओं को, जो केवल बिना शॉड वाली बीड़ियों का उत्पादन करते हैं, एक वर्ष में प्रथम 60 लाख बीड़ियों की निकासी (क्लीयरेंस) के संबंध में शुल्क की अदायगी से मुक्त करने का प्रस्ताव किया जाता है। मैं, बचाने वाली तम्बाकू, नमस्त्र और धूम्रपान के मिश्रणों के शुल्क में समुचित वृद्धि करने का भी प्रस्ताव करता हूँ। यह भी प्रस्ताव किया जाता है कि शॉड वाली निमित्त हुक्का तम्बाकू पर मूलानुसार 20 प्रतिशत की दर से शुल्क लगाया जाए।

112. एक अन्तरिम उपाय के तौर पर, मैं धूम्रपान मिश्रणों और निमित्त हुक्का तम्बाकू को छोड़ कर, शुल्कवत्त अनिमित्त तम्बाकू से बने उत्पादों के मामले में उत्पाद प्रवस्था में लगने वाले शुल्क में यथोचित राहत देने का प्रस्ताव करता हूँ।

113. सम्मानित सदस्यों को याद होगा कि श्री लक्ष्मीकान्त झा की अध्यक्षता में नियुक्त अप्रत्यक्ष कर जांच समिति ने जनवरी 1978 में अपनी रिपोर्ट का दूसरा भाग पेश कर दिया था। समिति ने कुछ स्थूल संकेत दिए थे जिनके आधार पर उत्पाद शुल्क टैरिफ को दीर्घावधि तथा अल्पावधि में युक्तियुक्त बनाने के लिए प्रयास किया जाना चाहिये। मैंने समिति की सिफारिशों पर बारीकी तथा सावधानी से विचार किया है। साधनों की आवश्यकता तथा अन्य व्यावहारिक तथ्यों का ध्यान में रखते हुए उत्पाद-शुल्क टैरिफ में अधिक फेर-बदल करना संभव नहीं है। इसके अलावा, हम बात की भी आशा है कि उत्पाद-शुल्क की मौजूदा प्रणाली में ज्यादा परिवर्तन कर देने से उत्पादन के विभिन्न क्षेत्रों के बीच संतुलन बिगड़ सकता है। तथापि समिति की सिफारिशों को कार्यान्वित करने की एक कार्यवाही के रूप में मैंने बहुत-सी उपभोक्ता वस्तुओं तथा सैयार उत्पादों पर लगने वाले उत्पाद-शुल्क की दरों के ढांचे में फेर-बदल करने का प्रयास किया है।

114. मैं शुरू में ही यह बता दूँ कि इस फेर-बदल के फलस्वरूप, इस समय जिन वस्तुओं के संबंध में उत्पाद-शुल्क में परिवर्तन किया गया है, उन पर उत्पाद-शुल्कों की प्रभावी दरों की संख्या को 28 से घटा कर 16 कर लिया गया है। मैंने शुल्कों के ढांचे में अधिक बुद्धिशीलता लाने के लिए भी इस अवसर का लाभ उठाया है और बिलास की तथा अर्द्धविलस की कई-एक वस्तुओं पर शुल्कों में वृद्धि की है। उत्पाद-शुल्क सौकर्य और प्रसाधन सामग्री (सुगंधित तेलों का छोड़कर) पर 63 प्रतिशत से बढ़ा कर 100 प्रतिशत आनामुक्ककों (एयरकंडीशनर) पर 105 प्रतिशत से बढ़ाकर 110 प्रतिशत, प्रणीत तथा आनामुक्कल यंत्रों (रेफ्रिजरेटिंग एण्ड एयरकंडीशनिंग मशीनरी) के पुर्जों पर 105 प्रतिशत से बढ़ाकर 125 प्रतिशत, स्टीरियो और हार्ड-फाई उपकरण पर 36.75 प्रतिशत से बढ़ा कर 40 प्रतिशत, अपेक्षाकृत अधिक कीमती टैरिफिजन

सेटों पर 21 प्रतिशत से बढ़ाकर 30 प्रतिशत, अधिक कीमती रेडियो तथा रेडियोग्राम पर 36.75 प्रतिशत से बढ़ाकर 40 प्रतिशत किया जा रहा है। मैंने इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों के संबंध में, मूल्यानुसार शुल्क की 15 प्रतिशत की विभेदी दर को कायम रखा है जहाँ लघु एककों के लिए ऐसी विभेदी दर लगती थी।

115. मैंने टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुओं पर लगने वाली शुल्क दरों में यथाचित वृद्धि करने के लिए भी इस अवसर का उपयोग किया है; इसके पीछे मेरी यही धारणा रही है कि इन वस्तुओं पर अधिकतर अनावर्ती किस्म का खर्च होता है और शुल्क का भार भी काफी लम्बी अवधि में फैल जाता है। इस श्रेणी में उत्पादशुल्क प्रेशर-कुकरों पर 10.5 प्रतिशत से बढ़ा कर 15 प्रतिशत, हस्पात के फर्नीचर पर 21 प्रतिशत से बढ़ा कर 25 प्रतिशत, घरेलू बिजली के उपकरणों पर 26.25 प्रतिशत से बढ़ा कर 30 प्रतिशत और सेफों तथा स्ट्रांग बक्सों पर 21 प्रतिशत से बढ़ा कर 35 प्रतिशत कर देने का प्रस्ताव किया जाता है।

116. मैंने साबुन दूध पेस्ट, दूध बुन और डिटजेंट जैसी कुछ उपभोक्ता वस्तुओं को भी इनके शुल्कों में वृद्धि करने के उद्देश्य में चुना है और हमने साथ ही इस बात का भी ध्यान रखा है कि विकेन्द्रीकृत क्षेत्र में लघु एककों द्वारा उत्पादित वस्तुओं पर इस वृद्धि का कोई बुरा असर न पड़े। उत्पादशुल्क घरेलू और लाठी साबुन पर 5.25 प्रतिशत से बढ़ कर 20 प्रतिशत, कम कीमती टायलट साबुन पर 10.5 प्रतिशत से बढ़ कर 15 प्रतिशत अधिक कीमती साबुन पर 15.75 प्रतिशत से बढ़ कर 20 प्रतिशत डिटजेंटों पर 13.13 प्रतिशत से बढ़ कर 20 प्रतिशत तथा दूध पेस्टों पर 10.5 प्रतिशत से बढ़ कर 25 प्रतिशत हो जाएगा। दूध बुनों पर भी 25 प्रतिशत की दर पर शुल्क लगाने का प्रस्ताव किया जाता है। मैं यहाँ साफ-साफ बता दूँ कि इन वस्तुओं पर उत्पाद-शुल्कों की दरों में वृद्धि करने का आंशिक उद्देश्य इस बात का सुनिश्चित करना है कि लघु निर्माता जिन्हें कर में छूट का लाभ प्राप्त है, इन वस्तुओं के बाजार में अपने हिस्से को बढ़ा सकें।

117. जहाँ तक खाद्य वस्तुओं का सम्बन्ध है, मैंने ग्राम जनता के उपभोग की वस्तुओं, जैसे खाद्य तेलों और वनस्पती पर कोई और बोझ नहीं डाला है। वास्तव में मैंने वनस्पती को विशेष उत्पादनशुल्क से मुक्त करके इस पर लगने वाले शुल्क को कम किया है। परन्तु मैंने तैयार भ्रष्टाचार परिरक्षित खाद्य पदार्थों इन्स्टेट, कॉफी, बिस्कुटों, संसाधित पनीर, कॉफी पाउडर, ज्यूइंग गम और चाकलेट जैसी वस्तुओं को, समाज में उनके उपभोक्ताओं के वर्गों का ध्यान में रखते हुए, उन पर शुल्क बढ़ाने के लिए उपयुक्त समझा है। इस प्रकार उत्पादन शुल्क इन्स्टेट कॉफी पर 21 प्रतिशत से बढ़ा कर 25 प्रतिशत तैयार भ्रष्टाचार परिरक्षित खाद्य पदार्थों बिस्कुटों तथा संसाधित पनीर पर 10.5 प्रतिशत से बढ़ा कर 15 प्रतिशत और कॉफी पाउडर, ज्यूइंग गम और चाकलेटों पर 10.5 प्रतिशत से बढ़ा कर 20 प्रतिशत कर दिया गया है। वातिन जल (एयरेटेड वाटर) के मामले में मादे सोडे पर शुल्क को 15.75 प्रतिशत से बढ़ा कर 20 प्रतिशत करने का प्रस्ताव किया जाता है। अन्य वातिन जलों के मामले में दो तरह की शुल्क दरें लागू किए जाने का प्रस्ताव है—एक तो 60 प्रतिशत की दर उन जलों के लिए जिनमें कैफीन हो और दूसरी 30 प्रतिशत की दर उन जलों के लिए जिनमें कैफीन न हो। मैं यह भी प्रस्ताव करता हूँ कि इस समय किसी एक वित्तीय वर्ष में प्रथम 50 लाख बोतलों की निकासी के सम्बन्ध में जो मौजूदा रियायती दर लागू होती है उसे वापस ले लिया जाए। किन्तु लघु निर्माताओं के हक में वातिन जलों में मौजूदा छूट मिलनी रहेगी।

118. उपभोक्ता वस्तुओं पर शुल्क दरों का पुनर्निर्धारण करने में मैंने कई वस्तुओं को विशेष उत्पादनशुल्क से मुक्त कर के उन पर शुल्क के भार को कम कर दिया है। मैं इस सम्बन्ध में खास तौर पर फ्लोरेसेंट लाइटिंग ट्यूबों का उल्लेख करना चाहूँगा जिनका अधिकतर उपयोग

सड़कों-गलियों में रोशनी की व्यवस्था करने के लिए किया जाता है और उनमें बिजली की खपत कम करने में सहायता मिलेगी, उन पर लगने वाले शुल्क को 42 प्रतिशत से घटा कर 30 प्रतिशत कर दिया गया है। प्रस्ताव है कि इस समय 5०० प्रति जोड़ा तक के मूल्य के कम कीमती जूने चप्पल आदि पर उत्पादन शुल्क की जो छूट दी जाती है वह छूट 10 रुपए प्रति जोड़ा तक की कीमत के जूने चप्पल आदि पर भी दी जाए।

119. मैंने व्यक्तिगत परिवहन साधनों पर लगने वाले शुल्क की दरों को भी युक्तिसंगत बना दिया है। मोपेडों पर, जिन्हें अपेक्षाकृत कम सम्पन्न लोग इस्तेमाल करते हैं और जिनमें कम ईंधन खर्च होता है भ्रष्टाचार से कम अर्थात् 10 प्रतिशत की दर से शुल्क लगेगा जबकि मौजूदा शुल्क लगभग 13.1 प्रतिशत है। स्कूटरों, मोटर-साइकिलों तथा नौन पश्चिमे वाले स्कूटरों पर 20 प्रतिशत की दर से शुल्क लगेगा, जबकि इन पर इस समय 13.13 प्रतिशत की दर से शुल्क लगता है, तथा कारों पर 25 प्रतिशत की दर से शुल्क भ्रष्टा करना होगा, जबकि शुल्क की मौजूदा दर 18.38 प्रतिशत है। टैक्सी के तौर पर चलाई जाने वाली कारों पर तथा ऑटो रिक्शाओं पर लगने वाले शुल्क की 10 प्रतिशत की रियायती दर को बढ़ाकर 15 प्रतिशत कर दिया जाएगा। शुल्कों को युक्तिसंगत बनाने की इस योजना के भ्रष्टाचार के रूप में, वार्तापत्रिक गार्डियों (कमिश्नियल वेहिकल्स) की दर में भी मामूली वृद्धि होगी, अर्थात् उसे 13.1 प्रतिशत से बढ़ा कर 15 प्रतिशत कर दिया जाएगा।

120. जहाँ तक निमित्त निवेश्य वस्तुओं (इनपुट) का सम्बन्ध है, मैंने अपने आपको, उनके उपयोग तथा सापेक्षिक महत्व को ध्यान में रखते हुए, मुख्य रूप से मौजूदा दरों के ढाँचे को सुधारने तक ही सीमित रखा है। इन परिवर्तनों का व्योरा बजट-पत्रों में दिया गया है।

121. अप्रत्यक्ष कराधान आंच समिति ने कराधान में सुधार करने का जो दूसरा सुझाव दिया है, वह यह है कि तैयार उत्पादों के निर्माण में इस्तेमाल की जाने वाली वस्तुओं पर लगने वाले शुल्क के सम्बन्ध में जो प्रोफार्मागित जमा की मुविधाएँ (प्रोफार्मा ग्रेटि कैमिलिटी) दी जाए इस समय ये मुविधाएँ एक सीमित क्षेत्र में ही सीमित हैं। इन मुविधाओं का और ज्यादा विस्तार करने में, जैसा कि समिति ने सुझाव दिया है, रास्ते सम्बन्धी बड़ी उपलब्ध पैदा हो जायेंगी और इसके अलावा तत्सम्बन्धी कार्य-प्रणालियों को चलाने का अतिरिक्त प्रशासनिक बोझ भी उठाना पड़ेगा। किन्तु औद्योगिक क्षेत्र का यह आग्रह है कि इस उपाय का आजमाया जाए, इसलिए मैं प्रयोगात्मक रूप में, प्रोफार्मागित जमा की मुविधा की व्यवस्था को इजीनियरी उद्योग के ऐसे कुछ उत्पादों पर लागू करने का प्रस्ताव करता हूँ, जिनके निर्माण में इस्तेमाल की जाने वाली वस्तुओं पर लगने वाले शुल्क का भार स्पष्ट है। ऐसा करने समय, मैंने अंतिम रूप से तैयार कुछ उत्पादों के शुल्कों में भी वृद्धि करने का प्रस्ताव किया है। इन परिवर्तनों का व्योरा बजट-पत्रों में उपलब्ध है।

122. केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क टैरिफ के ढाँचे के पुनर्व्यवस्थापन से संबंधित प्रस्तावों को लागू करने तथा कुछ प्रभावित वर्गों में थोड़ा परिवर्तन करने से, एक पूरे वर्ष में लगभग 100 करोड़ रुपए के निवल राजस्व की प्राप्ति होगी।

123. अब मैं साधन जुटाने के टोम प्रस्तावों का उल्लेख करूँगा।

124. उत्पाद-शुल्कों के क्षेत्र में, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण प्रस्ताव पेट्रोलि मूह के कुछ एक मुख्य उत्पादों से संबंधित हैं। सम्मानित सदस्य ज 1 है कि तेल तथा पेट्रोलियम निर्यातक देशों ने कच्चे तेल की कीमत में वृद्धि करने के एक खरणबद्ध कार्यक्रम की घोषणा की है। अभी तक भी हम काफी ज्यादा हद तक कच्चे तेल के आयात पर निर्भर रहते हैं, और कच्चे तेल की कीमतों में वृद्धि हो जाने के परिणामस्वरूप विदेशी मुद्रा के खर्च में काफी ज्यादा वृद्धि होने की संभावना है। वर्ष 1973

में कच्चे तेल की कीमतों में जो बहुत ज्यादा वृद्धि हुई थी, उसके कारण शुरू-शुरू में तो पेट्रोलियम के उत्पादों की खपत में कमी हुई, वित्तु खपत में काफी ज्यादा वृद्धि की प्रवृत्ति दिखाई दी है। उर्जा सम्बंधी एक ऐसी सशक्त नीति का विकास करने की दृष्टि से, जिसके अनुसरण में हमारे विदेशी मुद्रा के साधनों पर कम से कम दबाव पड़े, मैं निस्संदेह यही समझता हूँ कि ज्यादा महत्वपूर्ण पेट्रोलियम उत्पादों की खपत पर अंकुश लगाना बहुत जरूरी है। इसी महत्वपूर्ण उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए मैंने अपने राजस्व प्रस्तावों को तैयार किया है।

125. प्रस्ताव है कि मोटर स्पिरिट पर लगने वाले केन्द्रीय उत्पाद शुल्क को, जो इस समय 2253.88 रु० प्रति किलोमीटर है बढ़ा कर 2750.00 रु० प्रति किलोमीटर कर दिया जाए। चूंकि पेट्रोल की अधिकतर खपत समाज के ऊपरी वर्गों के लोग ही करते हैं, इसलिए इस वृद्धि के लिए मुझे कोई अफसोस नहीं है। मैं यह प्रस्ताव भी करता हूँ कि हाई-स्पीड डीजल तेल के शुल्क को, जो इस समय 404.04 रु० प्रति किलोलिटर है, बढ़ाकर 500 रु० प्रति किलोलिटर कर दिया जाए क्योंकि इसकी खपत में बड़ी तेजी से वृद्धि हुई है।

126. जैसा कि सम्मानित सदस्य जानते हैं पहले हाई स्पीड डीजल तेल में मिट्टी के तेल (केरोसीन) की मिलावट की जाती थी क्योंकि मिट्टी के तेल की कीमत कम थी। पिछले कुछ वर्षों से हमारा प्रयास यही रहा है कि इस प्रवृत्ति को यथासंभव इन दोनों उत्पादों के शुल्कों की दरों में समानता रखकर, रोका जाए। इसके अलावा हमें अभी हाल ही में मिट्टी के तेल का आयात करके ही काम चलना पड़ा है। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए मैं प्रस्ताव करता हूँ कि मिट्टी के तेल के शुल्क को जो इस समय 408.19 रु० प्रति किलोलिटर है बढ़ाकर 500 रु० प्रति किलोलिटर कर दिया जाए। मैं यह प्रस्ताव भी करता हूँ कि इसके साथ-साथ, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस के शुल्क की दर को भी, जिसे मुख्य रूप से शहरी तथा अर्ध-शहरी इलाकों में खाना पकाने के काम में इस्तेमाल किया जाता है, 262.50 रु० प्रति मेट्रिक टन के मौजूदा स्तर बढ़ाकर 400 रुपए प्रति मेट्रिक टन कर दिया जाए।

127. पेट्रोलियम के उत्पादों से संबंधित मेरे प्रस्तावों से केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क के अन्तर्गत 223.25 करोड़ रु० तथा सीमा शुल्क के अन्तर्गत 55.7 करोड़ रु० के अतिरिक्त राजस्व की प्राप्ति होने का अनुमान है।

128. इसके बाव, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क टैरिफ की अवशिष्ट शीपे मब 68 पर शुल्क की दर को 5 प्रतिशत के वर्तमान स्तर से बढ़ा कर 8 प्रतिशत मूल्यानुसार करने का प्रस्ताव है। इससे 100 करोड़ रुपए के अतिरिक्त राजस्व की प्राप्ति होगी। जैसा कि सम्मानित सदस्यों को मालूम है, मब 68 के अन्तर्गत आने वाली उन वस्तुओं पर अब लागू किए गए शुल्क को मुजरा करने की व्यवस्था पहले से ही मौजूद है जो कि ऐसी दूसरी वस्तुओं के निर्माण करने के काम में जाती हैं जिन पर उत्पाद शुल्क लगाया जा सकता है। इसलिए बचे हुए इस शुल्क का कोई खास बहू-स्थानिक प्रभाव पड़ने की आशंका नहीं है।

129. जैसा कि सदन को विदित है, मब 68 में बड़े वस्तुओं का उत्पादन करने वाले उन सभी लघु निर्माताओं को, जिनकी उत्पाद शुल्क योग्य वस्तुओं की निकासी पूर्ववर्ती वर्ष में 30 लाख रुपए से ज्यादा की नहीं थी, इस समय 30 लाख रुपए के मूल्य तक की पहली निकासियों पर वेय शुल्क से छूट मिलती है। इस आशय के अभ्यावेदन बराबर प्राप्त होते रहे हैं कि किसी भी लघु एकक की रियायत की पात्रता का आकलन करने के लिए मब 68 से भिन्न अन्य सवों में दर्ज वस्तुओं के मूल्य को शामिल नहीं किया जाना चाहिए। ऐसी मांग भी की जाती रही है कि निर्यात की निकासियों को भी शामिल न किया जाए ताकि लघु उद्योग क्षेत्र के एककों को निर्यात बढ़ाने के कार्य में प्रोत्साहन मिलता रहे। मैं इन मांगों के औचित्य को स्वीकार करता हूँ। इन मांगों को तथा मब

68 के अन्तर्गत शुल्क में की जाने वाली प्रस्तावित छूट को हटान में रखने हुए, मैं छूट दिए जाने की मौजूदा योजना को सुनिश्चित बनाने का प्रस्ताव करता हूँ। संशोधित योजना के अनुसार जो कि पहली अप्रैल 1979 से लागू होगी उन सभी लघु निर्माताओं को जिनकी मब 68 की वस्तुओं की, आन्तरिक उपयोग के लिए निकासी पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में 30 लाख रुपए के मूल्य से ज्यादा की नहीं थी 15 लाख रुपए तक के मूल्य की उनकी पहली निकासी पर मब 68 के अन्तर्गत लगने वाले शुल्क से पूरी छूट मिलेगी और 15 लाख रुपए से लेकर 30 लाख रुपए तक की निकासियों पर उनको 4 प्रतिशत की दर से शुल्क देना होगा जो कि इस मद के लिए प्रस्तावित शुल्क की दर से आधी है।

130. जैसा कि सम्मानित सदस्य जानते हैं, चूने हुए उद्योगों में उत्पादन की वृद्धि को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से उत्पाद शुल्क से छूट देने की जिस योजना की घोषणा 1976 में की गई थी वह 31-3-1979 को समाप्त होने वाली है। मैं इस योजना को इस तारीख से आगे जारी रखना नहीं चाहता। इस योजना की समाप्ति से 40 करोड़ रुपए का अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होने की आशा है।

131. मैंने इस अधिनियम का लाभ उठाकर बहुत-सी विद्यमान अधिसूचनाओं की समीक्षा की है और मैं चाहता हूँ कि उनमें से कुछ को संशोधित कर दिया जाए या वापस ले लिया जाए। इसका अधीन बजट-पत्रों में उपलब्ध होगा।

132. अतिरिक्त साधन खोज निकालने की अपनी कोशिश में, मुझे आवश्यकतापण, पुरानी वफादार सिगरेट का ही महारा लेना पड़ रहा है। मैंने पहले ही अनिमित्त प्रवस्था में तम्बाकू पर लगने वाले शुल्क को वापस लेने के प्रस्ताव का उल्लेख किया है, जमका बांझ सिगरेटों पर पड़ता है। लेकिन अब मैं सिगरेटों की शुल्क-दरों के ढांचे में इस तरह से समायोजन करना चाहता हूँ कि जिससे कि हम मद से 60 करोड़ रुपए की अतिरिक्त रकम और प्राप्त हो सके। इस उपाय में प्रत्याशित राजस्व की हिसाब में लेते हुए तथा निमित्त तम्बाकू के उत्पादों पर लगने वाले शुल्क की दरों के ढांचे को नया रूप देने में जिसका उल्लेख मैंने पहले किया है, बिक्री कर के बढ़ते अतिरिक्त उत्पाद शुल्क के राज्यों के हिस्से में एक वर्ष 18.31 करोड़ रुपए की वृद्धि होगी।

133. जैसा कि सम्मानित सदस्य जानते हैं, उत्पाद-शुल्कीय व्यवस्था को यत्नपूर्वक इस प्रकार से हस्तेमान में लाया गया है जिससे कि गैर-मशीनी क्षेत्र में वियासलाइयों के उत्पादन को बढ़ावा मिल सके। मैं, मशीनी क्षेत्र द्वारा बनाई जाने वाली वियासलाइयों के शुल्क को, जो कि इस समय 50 तैलियों की ढक्की के एक गुन पर 4.83 रुपए के हिसाब से लिया जाता है, बढ़ाकर 9.20 रुपए कर देने का प्रस्ताव रखकर इसी प्रक्रिया को और आगे बढ़ाना चाहता हूँ। मैं यह प्रस्ताव भी करता हूँ कि कुटीर एककों से भिन्न, गैर-मशीनी क्षेत्र पर लागू शुल्क की वर्तमान दर को, जो कि 4.52 रुपए है, पूर्णोक्ति कर के 4.50 रुपए कर दिया जाए। अतः तक कुटीर क्षेत्र के उद्योगों का सम्बन्ध है, प्रस्ताव है कि उन पर लागू शुल्क की दर को 3.36 रुपए से घटाकर 1.60 रुपए कर दिया जाए। मुझे पूरा विश्वास है कि इन सभी उपायों से गैर-मशीनी क्षेत्र में आमतौर से और कुटीर उद्योगों में खास तौर से उत्पादन की वृद्धि और भी तेज रफ्तार से होगी। आशा है कि एक वर्ष में, इन उपाय से 8 करोड़ रुपए के अतिरिक्त राजस्व की प्राप्ति होगी।

134. कुछ एक संगठित एककों में मशीनों में जो कालीन बनाए जाते हैं उनका उपभोग एक विशिष्ट वर्ग के लोगों तक ही सीमित है। मैं इस क्षेत्र के उत्पादन को बढ़ावा देने का कोई औचित्य नहीं समझता जबकि हमारे यहाँ पर बड़ी तादाद में कालीन बुनने वाले परम्परागत कारीगर मौजूद हैं जिनके कौशल को अन्तर्राष्ट्रीय व्यापि प्राप्ता है। इसलिए मैं नहीं चाहता कि मशीनी कालीनों के उत्पादन में वृद्धि करके हम बुनकरों

की आर्थीविका को खतरे में डाला जाए। इसलिए मैं प्रस्ताव करता हूँ कि इस प्रकार के मर्गानों से बने कार्बनों पर 30 प्रतिशत की दर से शुल्क लगा दिया जाए। साथ से बने कार्बनों को इस शुल्क से पूर्णतया मुक्त रखा जाएगा। इस प्रस्ताव से अनुमानतः 1.9 करोड़ रुपए के अनिश्चित राजस्व की प्राप्ति होगी।

135. उपर्युक्त उद्देश्य के अनुरूप और सूती कपड़ा तैयार करने वाले श्रम-प्रधान क्षेत्र को, जिसमें बिजली का प्रयोग नहीं होता, बढ़ावा देने के लिए प्रस्ताव है कि ब्रिज कास्मो के उन सूती फैब्रिको (बर्बो) पर जो पावर से चलाए जाने वाले करघों पर तैयार किए जाते हैं, लगने वाले मूल्यानुसार शुल्क की 8 प्रतिशत की रियायती दर को हटा दिया जाए। ताकि इस प्रकार के फैब्रिको पर मूल्यानुसार 12 प्रतिशत की उसी दर से शुल्क लगे जितना कि हमारे पावर से तैयार किए जाने वाले फैब्रिको पर लगता है।

136. यह सरकार हेडरूम (हथकरघा) क्षेत्र को प्रोत्साहन देने के लिए बतवश है। पावरलूम तथा मिश्रित मिलों द्वारा उत्पादित फैब्रिक के मुकाबले में हेडरूम से बने फैब्रिक की प्रतियोगी क्षमता में और ज्यादा सुधार करने की जरूरत है। इसलिए प्रस्ताव है कि कपास तथा मेषखोज के भारीक बड़े भाग के उत्पाद शुल्क में, जिसका हस्तेमाल मिश्रित सूती कपड़ा मिलों तथा पावरलूमों द्वारा किया जाता है मौजूदा दरों के लगभग 10 प्रतिशत की और वृद्धि कर दी जाए। इन परिवर्तनों का व्यौरा बजट पत्रों में दिया गया है। इन उपायों से लगभग 10 करोड़ रुपए के अनिश्चित राजस्व की प्राप्ति होने का अनुमान है।

137. 1978 के बजट में जो विशेष उत्पाद-शुल्क लगाए गए थे वे 31-3-1979 को समाप्त होने जा रहे हैं। प्रस्ताव है कि इन शुल्कों का प्रभावी बुनियादी शुल्कों के 1/20 वें भाग की वर्तमान दर पर एक वर्ष आगे तक जारी रख जाए। किन्तु इस शुल्क से उन मदों को मुक्त रखने का प्रस्ताव है, जिनके सम्बन्ध में शुल्क दरों को पुनः निर्धारित कर दिया गया है और नए शुल्क लगाए गए हैं। बिजली, कोयले तथा मद 68 की वस्तुओं पर इस समय जो छूट दी जा रही है उसे आगे भी जारी रखा जाएगा।

138. अब मैं सीमा-शुल्कों से सम्बन्धित प्रस्तावों का निरूपण करूंगा। इनमें से सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण प्रस्ताव उन सभी आयातित वस्तुओं पर लगने वाले प्रतिमसुलनकारी सीमाशुल्क की मौजूदा छूट को समाप्त करने से सम्बन्ध रखता है जो कि केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क टैरिफ की मद 68 के अन्तर्गत वर्गीकृत हैं। जब 1975 में उस टैरिफ में इस अवशिष्ट मद को दर्ज किया गया था, तब आयातित वस्तुओं को तदनुसृत प्रतिमसुलनकारी सीमा-शुल्क से छूट प्राप्त थी। यह छूट, जो शुरू में उस समय दी गई थी जबकि देशी वस्तुओं को 1 प्रतिशत मूल्यानुसार उत्पाद-शुल्क लगता था अब तक बराबर जारी रखी गई, हालांकि दर को उत्तरांतर 5 प्रतिशत तक बढ़ा दिया गया है। जैसा कि मैंने पहले बताया है, मैंने मद 68 के अन्तर्गत केन्द्रीय उत्पाद शुल्क को 5 प्रतिशत मूल्यानुसार से बढ़ाकर 8 प्रतिशत मूल्यानुसार कर देने का प्रस्ताव किया है। इस संबंध में तथा मद 68 में वर्गीकृत देशी वस्तुओं को संरक्षण देने के उद्देश्य से प्रस्ताव है कि आयातित वस्तुओं के सम्बन्ध में दी जा रही मौजूदा छूट को समाप्त कर दिया जाए। किन्तु इस छूट को समाप्त करने का प्रस्ताव रखकर मैंने परियोजना सम्बन्धी आयात के शुल्क से तथा मर्गानरी की उन मदों के शुल्क में भी कोई परिवर्तन करने का प्रस्ताव नहीं रखा है जिनके सीमा शुल्क को अभी हाल ही में घटाकर मूल्यानुसार 25 प्रतिशत इस आधार पर कर दिया गया था कि ऐसी मर्गानरी का उत्पादन देश में नहीं होता। इस उपाय से प्रतिमसुलनकारी शुल्क के रूप में 96 करोड़ रुपए के अनिश्चित राजस्व की प्राप्ति होगी।

139. खाद्य तेलों की पुनः तथा उनकी मांग में काफी ज्यादा अन्तर होने के कारण पहले इन तेलों का भारी मात्रा में आयात किया गया

था और आयात का मिलमिला अब भी जारी है। तेलहनों के देशी उत्पादकों को उनकी उपज की लाभकारी कीमत दिलवाने की सुनिश्चित व्यवस्था करने के लिए प्रस्ताव है कि ताड़ के तेल, रपसीड के तेल, सोयाबीन के तेल, सूरजमुखी के तेल तथा पामाकिन के तेल पर 12½ प्रतिशत मूल्यानुसार की दर से सीमा-शुल्क लगा दिया जाए। किन्तु उनको सहायक तथा प्रतिमसुलनकारी शुल्कों से छूट मिलेगी। आशा है कि इस प्रस्ताव से 34.5 करोड़ रुपए के अनिश्चित राजस्व की प्राप्ति होगी।

140. प्रस्ताव है कि अगले वित्तीय वर्ष में सहायक सीमाशुल्कों को मौजूदा दरों पर ही जारी रखा जाए।

141. केन्द्रीय उत्पाद-शुल्कों तथा सीमा-शुल्कों से सम्बन्धित मेरे प्रस्तावों से कुल मिलाकर एक पूरे वर्ष 606.14 करोड़ रुपए के निवल राजस्व की प्राप्ति होगी जिसमें से 413.15 करोड़ रुपये की राशि केन्द्र को और 192.99 करोड़ रुपए की राशि राज्यों को प्राप्त होगी।

142. जिन मामलों में परिवर्तन अधिसूचनाओं के द्वारा किए जाएंगे जो कि पहली मार्च 1979 से लागू होंगे, उन मामलों में ऐसी अधिसूचनाओं की प्रतियां ठीक समय पर भवा पटल पर रख दी जाएंगी।

143. सम्मानित सदस्यों को मान्य है कि प्रत्येक अन्तर्राष्ट्रीय यात्रा के सम्बन्ध में, जिसकी प्रदायगी भारतीय मुद्रा में की जाती है, यात्रियों से विदेश यात्रा कर भी वसूल किया जाता है। इस कर की प्रणामन व्यवस्था को सरल बनाने तथा इस कर के अपवर्धन की संभावनाओं को समाप्त करने के लिए मैं इस योजना का संशोधित करते हुए, मूल्यानुसार शुल्क के स्थान पर मात्रानुसार शुल्क लगाए जाने का प्रस्ताव करता हूँ। नई व्यवस्था को, तत्सम्बन्धी कानून बनाए जाने के बाद गद्यसंभव गीष्ट लागू कर दिया जाएगा। राजस्व प्राप्ति की दृष्टि से इस प्रस्ताव का कोई खान महत्व नहीं है।

144. अब मुझे कुछ शब्द अपने मित्र मंचार-मंत्री महोदय की ओर से भी कहने हैं। जैसा कि सम्मानित सदस्यों को मान्य है, हमारी बहुत सी डाक सेवाओं की इकाई लागत (यूनिट कौस्ट) उनसे प्राप्त होने वाले राजस्व से ज्यादा बैठती है। इसके अलावा दूर-संचार सेवाओं के आधुनिकीकरण पर बहुत ज्यादा पूंजी का निवेश करना पड़ता है। इन बातों को देखते हुए यह जरूरी मान्य होता है कि डाक तथा दूर-संचार की शुल्क-दरों में वृद्धि की जाए। बजट पत्रों के साथ ही एक जापन परिष्कृत किया जा रहा है जिसमें प्रस्तावित शुल्क दरों को दिखाया गया है। पत्रकार्ड (अन्तर्विषीय पत्र) तथा पत्र पर पांच पैसे ज्यादा खर्च करने पड़ेंगे। किन्तु पोस्टकार्ड की कीमत में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। जहां तक दूर संचार की शुल्क-दरों का सम्बन्ध है, 8 शब्दों के साधारण तार पर 2.25 रुपये लगेंगे जबकि इस समय इस पर 2.00 रुपए लगते हैं और प्रत्येक शब्द पर 30 पैसे देने पड़ेंगे जबकि इस समय 25 पैसे देने पड़ते हैं। किन्तु प्रेम टेलीग्राम की दर ज्यों की त्यों अपरिवर्तित रहेगी। प्रति निमाही 1750 "कालो" से ऊपर स्थानीय "काल" प्रभार 40 पैसे प्रति "काल" के हिसाब से लिए जाएंगे, जबकि इस समय, यह प्रभार 30 पैसे प्रति "काल" के हिसाब से लिए जाते हैं। जो और व्यौरा जापन में दिया गया है, उसका उल्लेख मैं यहाँ नहीं करूंगा। शुल्क दरों की इन वृद्धियों में, जिनकी विस विधेयक के पारित होने के पश्चात् सरकार द्वारा अधिसूचित तरीक से लागू किया जाएगा, अनुमानतः प्रतिवर्ष 57.96 करोड़ रुपए के अनिश्चित राजस्व होगी। 1979-80 में 48.30 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त होने का अनुमान है और इसे डाक तथा तार विभाग के आन्तरिक साधनों के अनुमानों में शामिल कर लिया गया है।

145. हमारे कर-प्रवर्धन में लगभग 605 करोड़ रुपए की प्राप्ति होगी जिसमें से 205 करोड़ रुपए की रकम राज्यों को मिलेगी और

बाकी 460 करोड़ रुपए केन्द्र के पास रह जायेंगे। आय कर-वृद्धियों से अनिवार्य निक्षेप के अन्तर्गत प्राप्त 160 करोड़ रुपए की प्राप्ति को हिमाचल में लेने के बाद भी, 1355 करोड़ रुपए का घाटा शेष रहेगा जिसे मैं पूरा किए बिना ही छोड़ने का प्रस्ताव करता हूँ। इतने बड़े घाटे से उत्पन्न होने वाली मुद्रास्फीति के संभावित प्रकोप का अंदाजा भी मैंने भर्त्सनात्मकता लगा दिया है। जालू वर्ग के बड़े हुए खाद्य उत्पादन से हमारे खाद्यान्न तथा अन्य वस्तुओं के विशाल भण्डारों से विदेशी मुद्रा प्राप्तित निधि में उपलब्ध विपुल धन-शक्ति से तथा पूँति की मौजूदा मुख्यस्थता और निर्वन्धनकारी मोद्रिक नीतियों को लागू जारी रखने के निर्णय से भरे अन्तर यह विश्वास उत्पन्न होना है कि हम लोग आगामी वर्ष में भी उचित सीमा तक कीमतों में स्थिरता बनाए रख सकेंगे।

146. इसके साथ ही मैं अपनी श्रम-माधना की समाप्ति पर आ पहुँचा हूँ। मैं इस सत्र में कृषि तथा ग्रामीण विकास और श्रम प्रदान उद्योग-धंधों के विकास पर ज्यादा से ज्यादा जोर देने की कोशिश की है, क्योंकि अब सभी हम बात को स्वीकार करते हैं कि केवल इसी एक तरीके से हम अपने देश में गरीबी और बेरोजगारी को दूर कर सकते हैं। किन्तु मैंने इस प्रक्रिया में बड़े उद्योगों तथा आधारभूत सुविधाओं की अग्रगण्यता नहीं की है। इसके विपरीत, मैंने उनको स्पष्ट प्रोत्साहन दिया है। किन्तु मुझे उन उद्योगों से कोई सहानुभूति नहीं है जो कि धनवानों की जरूरतों को पूरा करते हैं। ऐसे उत्पादन के लिए हमारे पास कोई जगह नहीं है जो श्रमियों की जरूरतों को पूरा करता हो और जो इस प्रकार हमारे समाज में विद्यमान विषमताओं की मूल अभिव्यक्ति हो।

147. जिस तरह की गरीबी हमारे देश में मौजूद है उसको एक-दम से दूर नहीं किया जा सकता। गरीबी दूर करने का काम एक लम्बी प्रक्रिया है जिसे समाज में जहाँ कहीं से उपलब्ध अतिरिक्त साधनों को जुटाकर, उनका बड़े पैमाने पर निवेश करके, बेहतर संगठन स्थापित करके और समुचित ज्ञान का विकास करके उसे समूचे देश में कृषि और सम्बद्ध व्यवसायों तथा ग्रामीण उद्योगों में काम करने वाले लाखों छोटे व्यक्तियों तक पहुँचा कर पूरा किया जा सकता है। हमारा अंतिम उद्देश्य केवल गरीबी को रद्द-महत् के स्तर का ऊँचा उठाना ही नहीं है, बल्कि एक ऐसे समाज का निर्माण करना है जिसके स्त्री-पुरुषों के पास काना-कोणन, साधन, कल्पनाशक्ति और सर्वोपरि आशा हो। मैं तो यही समझता हूँ कि यह सत्र इसी दिशा में बढ़ाया गया एक छोटा-सा कदम है। किन्तु इसकी सफलता वास्तव में इस बात पर निर्भर करती है कि उद्देश्य की बाँझनीयता और उसे प्राप्त करने के लिए परिश्रम करने की आवश्यकता के बारे में राष्ट्रीय स्तर पर मतभेद हो और समाज के शक्तिशाली एवं साधन-सम्पन्न वर्ग आवश्यक त्याग और बलिदान करने के लिए राजी हो। मैं अपेक्षित बलिदान और मत्तक्य करने के लिए इस सत्र का सहयोग चाहता हूँ।

ए० सी० निबारी, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF FINANCE
Department of Economic Affairs
(Budget Division)

BUDGET 1979-80

SPEECH OF DEPUTY PRIME MINISTER

AND MINISTER OF FINANCE

[No. F. 18(85)-B(D)/78]

New Delhi, the 28th February, 1979

Sir,

I rise to present the Budget for the year 1979-80.

2. The Economic Survey for 1978-79 placed before the House a few days ago presents a detailed account of the trends in the economy for the current year. I shall therefore confine my observations to a few salient aspects of the

economic situation in the context of which the budget has been formulated.

3. The performance of the Indian economy during the current year is a matter for great satisfaction. Agricultural production has continued at a record level for the second year in succession. This achievement is not due entirely to favourable seasonal factors. The increased production is in good part also the result of increased availability of irrigation and fertilizer, use of improved seeds, increased research and extension activity and extended price support and procurement operations. It is also in a great measure due to the energy and toil of millions of farmers who have undertaken investment, absorbed new technology, adopted new cultural practices and contributed to the general good by growing two ears of corn in place of one.

4. So long as there is great poverty and unemployment in the country, particularly in the rural areas, and agriculture has the largest potential for generating employment, and providing purchasing power to the large majority of the people, there can be no let up in the task of agricultural improvement. Our objective should be to raise productivity further by using improved technology and more inputs. This requires larger investment, greater effort in a variety of ways and better organisation.

5. Industrial production is also expected to register an increase of 7 to 8 per cent in the current year. This is due to an improvement in the production of a large number of industries. In particular, the increase in production has been sharp in electricity generation, food industries, electrical and non-electrical machinery, metal products, textiles and transport equipment. The over-all supplies of basic materials like cement, fertilizer, steel and non-ferrous metals were augmented by sizeable imports so that shortages did not act as a constraint on domestic growth.

6. If this rate of agricultural and industrial growth is to be maintained in the coming year, supplies of basic goods should increase through larger investment. That is why the Government is pushing ahead with a large investment programme in irrigation, electricity generation, cement, steel, fertilizers and transport.

7. Price stability which this Government achieved last year has continued through the current years as well. The wholesale price index on 10th February, 1979 was only 0.9 per cent above the level a year earlier and 0.4 per cent above the level two years earlier. Such a record of price stability in a period in which national income growth was about 11 per cent would be difficult to find elsewhere in the world. This has been brought about by well conceived supply and demand management policies. The role of increased agricultural and industrial production and a liberalised import policy in vital areas needs to be underscored in this regard. Simultaneously, a monetary policy restricting the flow of credit for speculative activities in the economy and directing the credit towards productive sectors has been pursued.

8. An expanding investment programme needs an increasing volume of resources. But resource mobilisation does not seem to match requirements. Government finds that there is a tendency on the part of various sectors of the economy to look upon tax concessions as the only way of improving their sagging fortunes. It must be realised that if the resources needed for development are to be raised without inflation there will have to be a greater readiness on the part of people who can bear further taxation to shoulder additional burden.

9. Another instrument of resource mobilisation has also not yielded the results expected. The surpluses of public sector undertakings have in 1977-78 been significantly lower than anticipated. It looks as if the results may not be appreciably better in the current year as well. Considering that total investment in these enterprises is of the order of Rs. 12,800 crores, this is disappointing indeed.

10. Savings in the economy have to increase if a rising level of investment is to be financed in a non-inflationary way. This can be achieved, among other things, by cutting down wasteful expenditure whether in Government or in the private sector. Economy in Government expenditure can be brought about by restricting non-development expenditure, particularly such subsidies as do not serve any specific social or economic purpose. Private saving should be raised by a ruthless curbing of luxury expenditure and adoption of a more austere life

style in tune with our traditional values and the hard facts of our economic life.

11. Exports which had recorded dynamic growth in the three years prior to 1977-78, have actually shown a decline in the first eight months of the current year. This disturbing trend is due to a number of factors, including restrictions on some of our more dynamic items in importing countries, recessionary tendencies in the developed world and increased domestic demand for certain exportables. It is most essential that we reverse the declining trend in total exports by pursuing an active promotion policy.

12. In addition to stressing the promotion of exports of manufactured goods, we should not lose sight of the fact that as a large agricultural country there is need to pursue an active policy with regard to the promotion of exports of agricultural products. A policy which will increase exportable surpluses of such items as fruits, vegetables, certain types of vegetable oils, oil extractions and spices, needs to be pursued vigorously because it will not only raise the incomes of the farmers but also generate additional employment in the rural areas.

13. The rising level of imports shows that the process of utilisation of reserves for development has begun. In addition to imports of a consumer goods like edible oil, those of developmental goods like steel, cement, fertilizer, non-ferrous metals have increased substantially. Import policy has been liberalised and wherever necessary, import duties have been reduced or waived altogether in order to facilitate imports of capital goods, spare parts, components and raw materials and thus remove constraints on production and investment.

14. The rate of growth of the country's foreign exchange reserves has slackened in the current year. This is partly the result of the trends in exports and imports and the slowing down of the growth of invisible earnings. It does not look as if we can expect a continuous growth in these if account is taken of the various national and international developments. Therefore, though the level of our reserves is high at present, there is need to husband them carefully.

Revised Estimates for 1978-79

15. Let me take up the Revised Estimates for 1978-79.

16. On the expenditure side there have been a number of post-budget developments which cast additional burdens on the Centre in the current year.

17. As the Hon'ble Members are aware, some of the State Governments, had, in recent years, been persistently overdrawing in excess of their borrowing entitlements from the Reserve Bank. To enable the States to start with a clean slate and avoid overdrafts in future, we had decided to extend special loans to the States to clear their overdrafts as at the end of 1977-78. The payments on this account amount to Rs. 555 crores. Assistance to the States for gratuitous relief to people affected by natural calamities had to be increased to Rs. 40 crores from the original provision of Rs. 10 crores.

18. To give the farmers a higher return on their produce, the procurement prices of rice, wheat and coarse grains were increased during the year involving additional expenditure of about Rs. 42 crores. After allowing for certain arrears payments to the Food Corporation and larger receipts following an increase in issue price of wheat from December 1978, expenditure on food subsidy during the current year will be Rs. 114 crores more than the Budget Estimate of Rs. 456 crores.

19. Expenditure on export assistance will be Rs. 130 crores higher than the Budget provision of Rs. 251 crores due partly to substantial spill over claims of previous year. Loss on sugar exports of 6.5 lakhs tonnes in 1978 will be Rs. 23 crores more than the original provision of Rs. 10 crores.

20. Non-Plan assistance on a larger scale than what was anticipated at the Budget stage had to be provided to a number of public sector units which experienced financial difficulties. Coal India will be requiring assistance of Rs. 173 crores, against the provision of Rs. 90 crores. Certain other units like the Fertilizer Corporation and National Textile Corporation also need substantial additional

assistance. As a result, non-Plan loans to the public undertakings will be Rs. 159 crores more than the Budget Estimate of Rs. 250 crores only.

21. As small savings fetched more than what was anticipated, loans to State Governments towards their share of collections will also be Rs. 165 crores more than the Budget provision of Rs. 300 crores; a part of the increase is on account of the spurt in collections towards the end of the previous year.

22. Defence expenditure in the current year is estimated at Rs. 2845 crores as against the Budget provision of Rs. 2945 crores.

23. The progress of Central Plan expenditure has been somewhat uneven and overall Budget support for Central Plan expenditure is estimated to be less by Rs. 201 crores as compared to the provision of Rs. 4520 crores made for it. The major shortfalls are anticipated in petroleum, fertilizer and telecommunication projects. Oil and Natural Gas Commission will require Rs. 63 crores less due to rephasing and postponement of certain works of its off-shore programme. Oil Industry Development Board will also require Rs. 58 crores less due to shortfall in petroleum sector's outlay. Fertilizer projects will require Rs. 36 crores less as compared to the original provision of Rs. 236 crores; the shortfall relates mainly to Trombay V and Cochin Phase II units and the new gas based fertilizer plant to be set up in Maharashtra. The outlay on telecommunication projects, which is mostly financed out of internal resources, is anticipated to be Rs. 46 crores less, mainly due to delay in receipt of equipment and stores.

24. A shortfall of Rs. 25 crores is anticipated in agricultural schemes. Certain agricultural schemes have not picked up the necessary tempo owing to delays in implementation by the State Governments or in formulation of the detailed schemes and inadequacy of necessary infrastructure. These problems are being tackled. Certain schemes have, however, made good progress. Hon'ble Members would be glad to know that the food for work programme is becoming a major instrument of rural development and employment promotion and the provision of Rs. 30 crores made for the scheme has been stepped up to Rs. 100 crores and is expected to generate 40 crores man-days of work during the year. Dairy development, which will also provide gainful employment and increased incomes in the rural areas, has been allocated Rs. 19 crores more over the Budget provision of Rs. 11 crores.

25. The current Budget provides Rs. 2761 crores for assistance to State and Union Territory Plans. As Hon'ble Members are aware, States affected by floods this year suffered serious erosion of resources and would not have been able to finance their approved Plan outlays without additional assistance from the Centre. It had accordingly become necessary to provide additional Plan assistance of Rs. 325 crores to those States. Rural Electrification Corporation had also to be provided with Rs. 39 crores more from the Budget to finance its approved Plan schemes which are in the State sector. According to Revised Estimates, Central assistance for State and Union Territory Plans in the current year is placed at Rs. 3112 crores.

26. As regards receipts in the current year, collections from small saving are expected to exceed the Budget Estimate of Rs. 460 crores by Rs. 140 crores, thanks to the sustained efforts of Central and State agencies concerned. Deposits of non-Government provident funds are also estimated to be Rs. 75 crores more than the Budget Estimate of Rs. 225 crores. Gold sales, for which no credit was assumed at the Budget stage, have fetched Rs. 86 crores. Recoveries of temporary credit extended in earlier years to bilateral trading countries will also show an improvement of Rs. 75 crores following larger imports from them.

27. Dislocation of industrial production in the eastern part of the country consequent on floods this year, and decline in the profit margins of certain major public sector undertakings have adversely affected receipts from corporation and income taxes. The receipts are estimated to be about Rs. 102 crores less than the Budget Estimate of Rs. 2577 crores. Union excise and customs duties taken together show an improvement of Rs. 145 crores. While, consequent on liberalisation of import policy and larger imports to meet

domestic requirements, customs duties are expected to yield Rs. 250 crores more than the Budget Estimate of Rs. 1860 crores, Union excise duties, on the other hand, will fetch Rs. 105 crores less than the Budget Estimate of Rs. 3229 crores. This shortfall is, among other things, due to lower realisation on sugar consequent on withdrawal of duty on khandasari sugar and fall in sugar prices after decontrol. There has been shortfall in excise revenue from kerosene, man-made fibres, aluminium and copper, which is, however, more than made up by larger receipts of import duties on these commodities.

28. Utilisation of external aid has slowed down due to a shift from programme to project assistance by multilateral aid giving agencies and also allocation of a greater proportion of bilateral assistance from some countries to specific projects. In both cases, the concerned projects are slow moving and, consequently, gross aid receipts are expected to be Rs. 447 crores less than the Budget Estimates. Steps are however being taken to accelerate the pace of disbursements.

29. Taking other variations in receipts and expenditure into account the overall deficit in the current year is estimated to be Rs. 1590 crores as against the original estimate of Rs. 1071 crores. This is exclusive of the additional burden of Rs. 555 crores cast on the Centre by the loans to certain States for clearing their past deficits which, being in the nature of a book adjustment, will not have an economic impact in the current year.

Budget Estimates for 1979-80

30. I shall now present the estimates of expenditure for 1979-80.

31. This budget reflects the impact of the recommendations of the Seventh Finance Commission which have been accepted by Government. While a larger transfer of resources to States in pursuance of the award of the Commission is eminently desirable for strengthening our federal polity, it creates serious problems for the Centre's finances in the short run. This budget seeks to cope with these problems.

32. The annual Plan of the Centre, States and Union Territories for 1979-80 would be Rs. 12511 crores compared with an approved total outlay of Rs. 11649 crores in 1978-79. This represents an increase of 7.4 per cent. However, in assessing these figures Hon'ble Members should bear in mind that an estimated sum of Rs. 835 crores has been transferred as committed expenditure from the Plan side to the non-Plan side in the Central and State Plans. Taking into account this transfer, the step-up in developmental effort in 1979-80 would be of a significant order.

33. The Central Budget for 1979-80 provides a sum of Rs. 7108 crores for the Central Plan and for assistance towards the Plans of States and Union Territories. A provision of Rs. 2300 crores has been made for Central assistance towards outlays of States' Plans, Union Territories' Plans, and the sub-Plans of Hills and Tribal areas, schemes of North-Eastern Council and Rural Electrification Corporation. Inclusive of their own resources, the Plans of States, Union Territories, North Eastern Council etc. will amount to Rs. 6099 crores in 1979-80 as against an outlay of Rs. 5985 crores in 1978-79.

34. The provision in the Budget for the Central Plan amounts to Rs. 4808 crores. Together with the internal and other resources of public sector undertakings amounting to Rs. 1604 crores, Central Plan in 1979-80 will, therefore, be of the order of Rs. 6412 crores, as against Rs. 5664 crores in 1978-79.

35. Subsequent to the determination of the outlays for the Central Plan and the Plans of the States for 1979-80, a decision has been taken at the recent meeting of the National Development Council to effect some modifications in respect of Centrally sponsored schemes. The funds now allocated for some of the Centrally sponsored schemes will be released for distribution among the States on the basis of a new formula. Consequential adjustments, in the Budget provisions for 1979-80 for these schemes, will be made in the course of the year.

36. As the Hon'ble Members are aware, the objective of eradicating poverty and unemployment is basic to our new development strategy. This calls for a radical restructuring of the priorities in our Plans, Agricultural and rural development have therefore been assigned the pride of place in our Plans. But Government recognises that the requisite degree of reorientation of development plans can be achieved only over a period of time. We propose, however, to accelerate the pace and thrust of programmes which have a material bearing on agricultural growth and promotion of employment.

37. The Plan outlay on agriculture and rural development has been raised from Rs. 1754 crores in 1978-79 to Rs. 1811 crores in 1979-80. An outlay of Rs. 258 crores has been provided for accelerating the integrated rural development programme in 2000 blocks covered by any of the special programmes and in 300 other blocks not covered by any of the special programmes so far. The focus will be on the improvement of the economic conditions of small and marginal farmers, agricultural labourers, rural artisans and scheduled castes and scheduled tribes. A provision of Rs. 50 crores is being made for the food for work programme. I have no doubt that I shall have to raise this figure steeply taking into account the experience in the current year. Such an increase will, however, have no inflationary impact as we will be drawing upon accumulated stocks of foodgrains.

38. Government does not have to stress in this House the importance of irrigation for agricultural development. The outlay on major, medium and minor irrigation projects including flood control for 1979-80 will be Rs. 1488 crores compared to Rs. 1401 crores in 1978-79. Most of this outlay will be in the budgets of the State Governments. The target for the creation of additional irrigation potential in 1979-80 has been fixed at 3.2 million hectares as against a target of 2.8 million hectares in 1978-79. In order to increase the pace of development of minor irrigation, a scheme is being worked out for extending the subsidy on minor irrigation, given at present only to small and marginal farmers, to farmers whose land holding is between 2 and 4 hectares, but at a reduced rate. To this end a provision of Rs. 10 crores is being made. The Plan provision for the minor irrigation programme will be supplemented with resources available from the Agricultural Refinance and Development Corporation. The financial support made available to the Agricultural Refinance and Development Corporation from the Central budget has been increased from Rs. 133 crores in 1978-79 to Rs. 159 crores in 1979-80.

39. In the context of the great importance we attach to rural development and employment-oriented programmes in rural areas, it is necessary to ensure that in the coming years the flow of institutional finance to rural areas will be smooth, steady and at reasonable rates of interest. In addition to many steps already taken, Government has decided to exempt the Agricultural Refinance and Development Corporation, the premier refinancing agency for agricultural term loans, from income-tax. This concession, together with other measures we are contemplating, will enable the Agricultural Refinance and Development Corporation to reduce the rate of interest at which it refines loans for minor irrigation and land development by about 1 per cent; the Reserve Bank will take corresponding steps to ensure that the full benefit of this reduction of about one per cent is passed on by the commercial banks to the ultimate borrower. As a result, farmers will find it cheaper and therefore more attractive to invest in minor irrigation and land development.

40. Hon'ble Members are aware that as part of the strategy of rural development, a National Dairy Development Programme, known as Operation Flood II, intended to raise the nutritional standards of the people, generate employment and augment incomes in rural areas through a viable subsidiary occupation had been approved earlier this year. An outlay of Rs. 32 crores has been provided in the Central Plan for 1979-80 for this programme. On completion it will provide gainful employment for about 10 million farm families and assure increased availability of milk to our people.

41. Rural electrification plays an important part in agricultural and rural development. The total outlay for the rural electrification programme will be Rs. 285 crores in

1979-80 An additional sum of Rs. 50 crores will be mobilised for this purpose through commercial banks, the Agricultural Refinance and Development Corporation and the Rural Electrification Corporation. Comparable figures in 1978-79 are Rs. 277 crores and Rs. 20 crores respectively. As against 22000 villages expected to be electrified in 1978-79, the target for 1979-80 has been set at 25000 villages.

42. With the increase in agricultural output there is an obvious need for increased storage to minimise wastage. A scheme is therefore being worked out to have subsidised storage facilities in rural areas. This will have two fold benefits: grain can be stored near the place of production thus reducing wastage and it will reduce the cost of storage for Government because godowns can be built cheaper and the cost of holding inventories will be borne by the farmers.

43. This Government is committed to the acceleration of the rural water supply programmes so as to make safe and reliable drinking water available in all problem villages. The Central Plan for 1979-80 includes a provision of Rs. 80 crores for this programme as against Rs. 60 crores allocated in 1978-79. After this Government came to power in March 1977, 18000 villages were provided with water supply in 1977-78. The target for 1978-79 is 27000. I wish to assure the House that Government will have no hesitation in allocating more funds for this purpose if the programmes make faster progress.

44. Economic exploitation and social discrimination against scheduled castes and scheduled tribes will not cease unless programmes for their development are built upon a sound economic basis. Therefore Central ministries and State Governments have been asked to incorporate a special component in their Plans for 1979-80 for these categories so that they may secure an adequate flow of benefits from the various sectoral programmes. The outlay on welfare programmes for scheduled castes and other backward classes will be Rs. 117 crores in 1979-80.

45. A provision of Rs. 70 crores has been made for the tribal sub-plan for 1979-80. This will supplement the flow of funds from State Governments under different heads of development. The States would also be receiving grants under the recommendations of the Seventh Finance Commission for providing incentives to their staff working in the difficult conditions in the tribal areas.

46. The development of village industries is an important component of the Central Plan. A provision of Rs. 193 crores has been made in 1979-80 in the Central sector as against Rs. 140 crores originally provided for in the current year. This outlay would be supplemented by suitable provisions in the State Plans and by institutional resources available on easy terms and conditions.

47. Handloom is our most important village industry. There are nearly 4 million handlooms providing employment to about 10 million people. They produced 2500 million metres of cloth in 1978-79 and the target for 1979-80 is 2700 million metres. A provision of Rs. 28 crores is being made in 1979-80 to organise weavers into cooperative societies, to enable apex cooperative bodies in this sector to do better marketing and to promote intensive development for export.

48. In keeping with the Government's policy of extending postal services in rural areas, it is proposed to open 5000 new post offices and provide 10,000 postal counters through mobile post offices in 1979-80. Outlay on telecommunications will be Rs. 359 crores in 1979-80 with greater emphasis than hitherto on extending these facilities to rural areas.

49. Care has also been taken to provide adequately for the development of the basic infrastructure on which the progress of agriculture and industries alike would be dependent. Thus the provision for power, coal, fertilizers and chemicals, minerals, petroleum, steel and roads and railways has been increased from Rs. 2733 crores in the Central Plan for 1978-79 to Rs. 3122 crores in 1979-80.

50. The growth of power production has an important role to play in the development of agriculture as well as industry. Allocation for the power sector in 1978-79 had been stepped

up substantially to Rs. 2217 crores. The tempo of development is sought to be speeded up still further in 1979-80 and an outlay of Rs. 2466 crores is being provided. The bulk of the Plan provision for power will be in the State Plans but an allocation of Rs. 382 crores is for power projects in the Central sector. A major start in 1979-80 will be the super thermal station at Farakka. It is expected that 3000 MW generating capacity will be added in 1979-80 as against 2500 MW in the current year. The facilities for distribution of power are also being improved.

51. Self-sufficiency in fertilizer production is an important objective of the Government policy. A provision of Rs. 254 crores for investment in fertilizer plants has been made in the Plan for 1979-80. This will cover expenditure on a number of on-going projects which will raise production in the public sector from 12 lakhs tonnes of nutrients this year to 20 lakh tonnes in 1979-80. Also, starts will be made on two off-shore gas based plants on the west coast and an additional gas based unit in Assam.

52. The demand for steel has increased by about 15 per cent in the current year due to increased activity and investment in the economy. The increased production of mini steel plants has averted a serious shortage which would have otherwise occurred. An outlay of Rs. 600 crores is being made for the steel sector in 1979-80. It has to be viewed in the context of the growing demand. This provision will enable work on the expansion of Bokaro and Bhilai Plants and on the new plant at Salem to be continued.

53. Coal is as basic to our development as power and there is an urgent need to raise its production. Coal production in the current year is estimated not to exceed a figure of 102 million tonnes as severe floods affected production. The allocation for the coal sector has been raised from Rs. 267 crores in the current year to Rs. 346 crores in 1979-80.

54. Oil is an equally important source of energy and Government attaches great importance to the exploration and development of oil fields so that our dependence on imported oil is minimised. The development of Bombay High will be substantially completed next year. With the commissioning of the 3 million tonne expansion at the Koyali refinery, the country's refining capacity has touched 30 million tonnes per year. Allocations to this sector in 1979-80 will be Rs. 622 crores.

55. Roads are of vital importance to the nation and a provision of Rs. 120 crores is proposed for 1979-80 for national highways, strategic roads, roads in the border areas in the north and roads of Inter-State economic importance. This will be supplemented by allocations from the State Plans to cover State highways and district and rural roads.

56. In our country urbanisation has led to a growth of slums and squatter settlements. Essential facilities like water supply, community latrines and baths, wide and paved streets and provision of street lighting have been badly lacking for these people. Government has decided therefore to pursue actively a policy of slum improvement. Against a total expenditure of Rs. 43 crores on slum improvement in 1974-78, an outlay of Rs. 190 crores has been envisaged in the period 1978-83. The States will have to push through this programme in a big way. If they undertake to mobilise additional resources for this purpose by taxing the affluent sections in the urban areas, Government will be happy to supplement their efforts. Government will examine in consultation with the States how the slum improvement programme can be accelerated so as to alleviate the living conditions of the urban poor.

57. In realigning the priorities in the educational sector, Government attaches the highest importance to the education of the masses. The provision for adult education in the Central Plan for 1979-80 is being accordingly increased and comes to nearly 20 per cent of the total outlay of Rs. 84 crores for education in the Central Plan.

58. It is now widely accepted that the programmes of development of agriculture or rural industries will not make sufficient progress unless the rural population acquires the relevant skills. Very little headway has, however, been made in the training of rural youth to acquire these skills. This is partly because of a lack of an effective training programme and partly a lack of proper organisation linking skills with

capital. Since such training is an essential precondition of the success of the production programme, Government proposes to make financial provision for a programme of 'training rural youth for self employment' in the course of the year as soon as the details of such a programme are worked out.

59. There is little doubt that the growth of population at the present rate needs to be checked if economic development is to lead to a perceptible increase in the standard of living of our people. Unfortunately, as a result of the wrong approach to family planning followed in the past, this programme has suffered a serious set back. It should be our endeavour to put the newly introduced family welfare programme on a sound footing so that the national objective of reducing the birth rate to 30 per thousand in 1982-83 from the current level of 33 per thousand may be achieved. The Community Health Workers Scheme which was started in October 1977 in 741 primary health centres was a significant innovation of the Janata Government in extending elementary medical care to rural areas. It is proposed to cover a third of the country under the scheme in 1979-80 and the entire country by 1982-83.

60. Non-Plan expenditure has been limited to what is strictly necessary keeping in view the need for economy consistent with efficiency.

61. Defence expenditure is estimated at Rs. 3050 crores as against Rs. 2845 crores in the current year.

62. Provision for food subsidy at Rs. 560 crores will be Rs. 10 crores less than in the current year. Rs. 448 crores have been provided next year for fertilizer subsidies as against Rs. 319 crores in the current year.

63. Debt service charges at Rs. 2161 crores will be about Rs. 304 crores more than in the current year, the increase being mainly on account of internal debt.

64. Statutory grants to States will be Rs. 232 crores as compared to Rs. 514 crores in the current year. The provision next year is based on the recommendations of the Seventh Finance Commission. The Commission has also recommended additional grants to certain States to cover their net interest liability and for upgradation of standards of administration. I have not, at this stage, included any provision for payment of grant-in-aid for these purposes and shall come before the House with request for supplementary funds after the action programmes for schemes of upgradation are drawn up and finalised by the State Governments concerned and the net interest liability assessed as recommended by the Commission.

65. Government is sure that Hon'ble Members will share its concern at the growing volume of Government expenditure. It is therefore important to contain the growth of this expenditure and also to ensure that the funds are utilised effectively for the promotion of the common good. Government has therefore decided to appoint a Commission with suitable terms of reference to conduct a comprehensive inquiry into Government spending. It will, among other things, examine the impact of public expenditure on the promotion of growth and reduction of poverty and recommend ways and means of making public expenditure more effective in solving the problem of poverty.

66. Coming now to Receipts, gross tax revenue in 1979-80 at existing rates of taxation is estimated at Rs. 10822 crores, showing an increase of Rs. 658 crores over the Revised Estimates for the current year. Of this increase, Union excise duties will contribute Rs. 381 crores and corporation and income taxes Rs. 248 crores.

67. As mentioned earlier, substantially larger devolution of Central taxes and duties will have to be made to the States from the next financial year in accordance with the recommendations of the Seventh Finance Commission. At the present level of taxation, States' share next year is estimated at Rs. 3235 crores which is Rs. 1278 crores more than in the current year. Consequently, Centre's net tax revenue, at Rs. 7587 crores, will be Rs. 620 crores less than in the current year.

68. Market loans will yield Rs. 1850 crores as against Rs. 1653 crores in the current year. Net external assistance, after meeting repayment and interest liabilities, is estimated

at Rs. 878 crores, including drawings against new credits. Small savings collections will fetch Rs. 650 crores. Loan repayments by States, excluding ways and means advances, are placed at Rs. 554 crores as against Rs. 754 crores in the current year. The decline is due to debt rescheduling recommended by the Seventh Finance Commission.

69. The total receipts of the Central Government for 1979-80 will be Rs. 16551 crores. Total expenditure for the coming year will be Rs. 18526 crores. The overall budgetary gap at the existing rates of taxation will thus be Rs. 1975 crores.

PART B

70. I now come to my proposals on fresh taxation.

71. A gap of this magnitude cannot obviously be covered without a large tax effort. However, in addition to mobilising the require resources, my tax proposals aim at three objectives which, I think would be acceptable to everyone in this House. In a country in which the bulk of the population lives below the poverty line disparities in income have to be minimised. Such disparities lead to luxury consumption which affects the propensity to save and the will to work hard. Therefore, tax policy should seek to reduce such disparities.

72. Secondly, they aim at increasing production and avoiding waste. Poverty elimination requires primarily an increase in production. Since resources are scarce, tax policy should prevent a diversion of resources to wasteful and unproductive uses and conserve them for productive purposes. It should also discourage such consumption as is positively injurious to people's health.

73. Thirdly, they aim at eliminating unemployment and underemployment by stimulating agricultural production, by encouraging labour intensive techniques of production and by improving the competitive capacity of small scale and cottage industries in relation to large scale industry.

74. Let me take up direct taxes first.

75. I propose to raise only the rate of surcharge for Union purposes on income-tax in the case of all categories of non-corporate taxpayers from 15 per cent to 20 per cent. The effect of this proposal will be to raise the marginal rate of personal income-tax from 69 per cent at present to 72 per cent. This measure will yield an additional revenue of Rs. 46 crores in a year. The accretion during 1979-80 will, however, be of the order of Rs. 37 crores only. This is a small sacrifice I am asking the 35 lakh taxpayers, who constitute an insignificant proportion of the total population, and who receive a substantial share of the country's income, to make for their poorer fellow citizens.

76. I am aware of the views of the State Governments against recourse to surcharge for Union purposes as the revenue accruing from surcharge is not shareable with the States. But in framing my other fiscal proposals I have taken care to see that States get their legitimate share of the gains from the additional tax effort of the Centre.

77. Under the rate of schedule prescribed in the Finance Act, 1978, in cases where the taxable income exceeds the exemption limit by a small margin, the tax liability is limited to 70 per cent of the excess over Rs. 10,000. This provision operates rather harshly in some cases. In order to provide for a smoother progression in marginal cases, I propose to limit the tax payable in such cases to 30 per cent of the excess over Rs. 10,000. This will benefit individuals having incomes up to Rs. 12,000.

78. In view of the imperative need for resources, I propose to continue the Compulsory Deposit Scheme for Income-tax Payers for a further period of two years. This will generate additional resources to the tune of Rs. 160 crores during the financial year 1979-80.

79. Inequalities of wealth have even less justification than inequalities of income. I, therefore, propose to raise the rates of wealth-tax on high slabs of net wealth. The rate will now be 3 per cent, as against the current rate of 2.5 per cent, on the net wealth between Rs. 10 lakhs and Rs. 15 lakhs and 5 per cent, as against 3.5 per cent, on the net wealth over Rs. 15 lakhs. The rates of wealth tax on slabs upto Rs. 10 lakhs will remain unchanged. There will be

corresponding changes in the rates applicable to Hindu undivided families having one or more members with independent net wealth exceeding the exemption limit. These changes will yield an additional revenue of Rs. 6.6 crores in a year. Since, however, the new rates of wealth-tax will apply prospectively from the assessment year 1980-81, there will be no accretion to revenue during 1979-80.

80. It has to be recognised that by merely adjusting direct tax rates we cannot reduce disparities in income and wealth to tolerable levels. As the House knows, tax evasion which is the basic cause of generation of black money greatly affects the progressive impact of direct taxes. Black money is a corrosive influence which works through the entire economy. It is important that this scourge is fought through the effective implementation of our tax laws. I wish to assure the House that I shall address myself to this task with the utmost zeal and vigour.

81. As I am raising the surcharge on income-tax on personal incomes, I think the corporate sector should also be required to contribute a little more to the exchequer. I accordingly propose to raise the surcharge on income-tax in the case of companies from 5 per cent to 7.5 per cent. This will not cast a heavy burden on them, because the effective rate of taxation on corporations is lower than the nominal rates. This measure will yield an additional revenue of about Rs. 35 crores in a year. The accretion during the year 1979-80 will, however, be of the order of Rs. 28 crores only.

82. The scheme of taxation of capital gains was modified in 1977 in several directions. One of the changes made was to provide for exemption from income-tax on long-term capital gains if the sale proceeds of any asset were reinvested within six months in certain preferred assets. Since asset owners secure capital gains largely through no effort on their own part, this exemption confers an unfair advantage on asset holders as compared to income earners and thus contributes to the disparity in society. I, therefore, propose to withdraw this exemption of capital gains in respect of transfers made after 28th February, 1979. This measure will yield an additional revenue of Rs. 14 crores annually. Since, however, advance tax is not payable in respect of capital gains, there will be no accretion to revenue during the year 1979-80.

83. The present concessions in respect of long-term savings through life insurance premia, provident fund contributions and other approved forms of savings, though they subserve certain desirable social and economic objectives, give a disproportionately large tax benefit to taxpayers in higher income brackets. At present, 100 per cent deduction is allowed in respect of first Rs. 5,000 of qualifying savings, 50 per cent on the next Rs. 5,000 of such savings and 40 per cent on the balance. Under my proposal, while the first Rs. 5,000 of qualifying savings will continue to be eligible for 100 per cent deduction the deduction in respect of the next Rs. 5,000 of such savings will be reduced to 35 per cent and in respect of the balance to 20 per cent. This measure will yield Rs. 9.6 crores annually. The accretion during the financial year 1979-80 will, however, be Rs. 7.6 crores.

84. I propose to lower the threshold for payment of advance tax by the registered firms from Rs. 30,000 to Rs. 20,000. This measure will yield an additional revenue of Rs. 12 crores during 1979-80.

85. The large scale unemployment in the country requires the promotion of labour intensive techniques instead of capital intensive techniques. While it may be true that in some industries the choice of techniques is limited, our preference should be for labour intensive methods of production wherever feasible. Our fiscal laws and tax concessions in particular should be so designed as to foster production techniques which enlarge opportunities for employment.

86. I, therefore, propose to appoint an Expert Committee of economists and tax administrators to study the impact of concessions provided for in our tax laws—particularly those relating to corporation tax and Central Excise—on the techniques of production used in industry and make recommendations which will encourage the adoption of labour intensive methods of production. The composition of the Committee and its terms of reference will be settled soon and it

will be asked to submit its Report with the least possible delay.

87. One of the tax concessions which is related to the employment of capital is the "tax holiday" provision in the Income-tax Act. This concession is at present available in respect of all industrial undertakings that go into production before 1st April, 1981. I propose to withdraw this concession in the case of industrial undertakings engaged in non-priority industries listed in the Eleventh Schedule to the Income-tax Act, if they go into production after 31st March, 1979.

88. In recent years, commercial banks, particularly public sector banks have been asked to reach out into the rural areas and to expand rural credit, in order to promote rural banking and to assist the scheduled commercial banks. In making adequate provisions from their current income to provide for risks in rural advances, I propose to amend the Income-tax Act to grant a deduction in respect of provisions made for bad and doubtful debts by scheduled commercial banks relating to advances made by their rural branches. Such a deduction will, however, be limited to 1.5 per cent of the aggregate average advances made by the rural branches. This measure will result in a revenue loss of Rs. 12 crores during 1979-80 but it will be in a good cause.

89. I have earlier referred to the exemption from the corporation tax which I wish to extend to the Agricultural Refinance and Development Corporation. This is in line with a similar exemption already being enjoyed by the Industrial Development Bank of India. This decision will result in a revenue loss of Rs. 5 crores annually. The loss during 1979-80 is estimated at Rs. 10 crores because advance tax paid during 1978-79 also is refundable.

90. At present, expenditure incurred by companies and co-operative societies on approved programmes of rural development qualifies for deduction in computing their taxable profits. For this purpose, the programme has to be approved by the "prescribed authority", which is an Inter-Ministerial Committee headed by the Secretary, Ministry of Agriculture and irrigation. Companies and co-operative societies have shown considerable interest in rural development programmes. To expedite the clearance of such schemes of rural development, I propose to provide that they will henceforth be approved at the State level by a Committee consisting of the Commissioner of Income-tax and a senior officer of the State Government nominated by it.

91. I also propose to exempt from income-tax donations made by tax-payers to approved institutions engaged in imparting training to persons to equip them for implementing rural development programmes.

92. At present, taxpayers engaged in business or profession alone are entitled to 100 per cent deduction in respect of donations made to approved institutions engaged in carrying out programmes of rural development. I propose to extend this concession to other categories of taxpayers as well. A similar dispensation will be extended to donations for scientific research made to approved scientific research associations, universities, colleges and other institutions.

93. It is also proposed to provide that insurance premia paid by federal milk co-operative societies for insuring cattle belonging to members of affiliated primary co-operative societies shall be allowed to be deducted in computing their taxable profits.

94. In order to promote the cultivation of mushrooms, it is proposed to exempt from income-tax one-third of the income derived from the business of mushroom growing under controlled conditions, or Rs. 10,000 whichever is higher.

95. As Hon'ble Members are aware, the Finance (No. 2) Act, 1977 has conferred exemption from income-tax on the Khadi and Village Industries Commission. It is now proposed to exempt from income-tax the income of the State Khadi and Village Industries Boards set up under the State Acts.

96. Consumer co-operative societies have been doing commendable work in supplying goods to consumers at reasonable prices. In order to encourage the development of such societies so that they can play a proper part in the public distribution system that is sought to be developed, it is proposed to raise the quantum of tax-exempt profits in the case

of such societies from the present level of Rs. 20,000 to Rs. 40,000.

97. The scope of section 35B of the Income-tax Act relating to export markets development allowance was curtailed last year. I have referred earlier to the decline in exports in the current year and the need to promote them. Therefore to enable exporters to develop export markets on a long-term basis, it is proposed to liberalise the scope of the export markets development allowance. A weighted deduction under section 35B of the Income-tax Act will now be available to all exporters at a uniform rate of 133.3 per cent of the qualifying expenditure. For this purpose, expenditure on advertisement or publicity outside India in respect of the goods, services or facilities dealt in or provided by the taxpayer in the course of his business will be included in the qualifying expenditure. This concession will result in a revenue loss of about Rs. 5 crores annually. The loss in 1979-80 will, however, be of the order of Rs. 4 crores.

98. In order to encourage the writing of University level text books in Hindi and other Indian languages, I propose to allow a deduction equal to 25 per cent of the income derived by the authors of such books. Authors of dictionaries and encyclopaedias in these languages will also get the benefit of a similar deduction in the computation of their taxable income. This concession will be available for the assessment year 1980-81 and four subsequent years.

99. While I want to step up the drive against tax evasion, I also would like to promote greater expedition in the settlement of income-tax cases. At present, the Income-tax Settlement Commission is debarred from proceeding with a case if the Commissioner of Income-tax objects to the application being proceeded with on certain grounds. The Direct Tax Laws Committee has recommended that the application for settlement should be rejected only after the Commission is satisfied that the objection has been raised by the Commissioner on proper and valid grounds. It is proposed to implement this recommendation subject to the safeguard that before overruling the objection raised by the Commissioner of Income-tax, the Settlement Commission should hear him.

100. The Direct Tax Laws Committee has also proposed certain amendments to the Income-tax Act and the Wealth-tax Act with a view to plugging some loopholes in the provisions relating to prevention of tax avoidance through intra-family transfers of income and wealth. I have accepted their recommendations and given effect to them through the Finance Bill.

101. As I mentioned earlier the second objective of my proposals is to prevent the life style of the affluent sections from having an adverse impact on saving and investment through the demonstration effect. In this connection, the lavish manner in which expenditure is incurred on accommodation and entertainment in luxury hotels calls for serious notice. With a view to checking such conspicuous consumption in luxury hotels, it is proposed to levy a new tax on the gross receipts of hotels. Since it is my intention that States should continue to levy sales tax as hitherto on items of food and drink supplied to guests in hotels, the sale proceeds of these items will not be included in the tax base. The details of this new measure are being worked out and the necessary legislation in this regard will be introduced in Parliament soon.

102. Other changes being made in the Income-tax law through the Finance Bill are of minor significance and are largely in the nature of clarification and rationalisation of existing provisions.

103. The total addition to revenue from all these tax measures will be Rs. 101.2 crores in a full year and Rs. 58.6 crores during 1979-80. Of this, about Rs. 12 crores will accrue to the States as their share in 1979-80. Besides, additional resources of Rs. 160 crores will accrue in 1979-80 from the continuance of the Compulsory Deposit Scheme for Income-tax Payers.

104. I now turn to indirect taxes

105. I would like to straightaway indicate the more significant reliefs in excise duties which I propose to provide. The Central excise duties on all chemical fertilizers, will be reduced to 50 per cent of the existing rates. This will mean that the basic Central excise duty on urea, which is the

most important chemical fertilizer, will be reduced from 15 per cent ad valorem to 7-1/2 per cent ad valorem; that on single and triple super phosphate fertilizer will be reduced from 7.5 per cent to 3.75 per cent ad valorem. This reduction will also be correspondingly reflected in the counter-vailing duties leviable on imported chemical fertilizers. With this change, it should be possible to reduce the price of urea by about Rs. 100 per tonne. The prices of other kinds of fertilizers will also become lower with reference to the excise duty relief now announced. This decision would result in a sacrifice of revenue of Rs. 75.6 crores under Central excise and Rs. 30 crores under customs.

106. Although the number of electric pumpsets is increasing rapidly with increasing rural electrification, farmers have still to use pumpsets driven by diesel engines in large parts of our country. As a measure of relief to this large class it is proposed to reduce the excise duty on light diesel oil from the existing level of Rs. 155.72 per kilolitre to Rs. 75 per kilolitre. Government is aware that only 45 per cent of this oil is used in the agricultural sector. Since it is difficult to monitor end use and a significant quantity of even the balance is used for generating power and by small industry, it is proposed to extend the benefit of this reduction in excise duty to all users without any distinction. The loss to the exchequer on account of this concession will be Rs. 12.40 crores per annum.

107. It is also proposed to exempt power tillers imported by State Agro-Industries Corporations and the Central Government totally from customs duty as these implements can promote agricultural production in small holdings. Hon'ble Members may be aware that indigenously manufactured power tillers are already exempt from Central excise duties.

108. Pipes made of PVC resins can reduce seepage and wastage of water in fields and thereby increase the effectiveness of irrigation. Since I wish to make this raw material available at cheaper prices for the manufacture of PVC pipes for irrigation and at the same time prevent a misuse of concession for other purposes, it is proposed as an experimental measure, to exempt PVC resins imported for the purpose from the customs duties as soon as the modalities of a scheme which will serve both the objectives have been worked out.

109. I would also refer to the relief in the field of drugs and medicines. It is proposed to fully exempt from customs duties 22 specified bulk drugs required for the formulation of life saving drugs, and to reduce the customs duty on 17 specified bulk drug intermediates from a total of 75 per cent ad valorem to 25 per cent ad valorem. On the excise side, it is proposed to exempt patent or proprietary medicines, including life saving drugs, from the levy of the special excise duty. Taking these measures together, the revenue sacrifice is estimated to be of the order of Rs. 7.04 crores a year.

110. I now turn to a proposal of far reaching significance. This concerns unmanufactured tobacco, excise on which dates back to the year 1943. This levy brings the excise machinery into contact with a large number of growers and licensees. It is proposed to completely exempt unmanufactured tobacco from excise duties, including additional excise duties and thus, relieve at one stroke, nearly a million tobacco growers, curers, small dealers and warehouse licensees from excise control. I have no doubt that this bold decision to do away with a vexatious levy—a legacy of the colonial era—will be widely welcomed by farmers in the tobacco growing tracts of our country. This measure would involve loss of central excise revenue of the order of Rs. 121.20 crores. I, however, propose to recoup Rs. 115.71 crores of this loss through suitable upward adjustments in the rates of duties on manufactured tobacco products.

111. I shall touch upon cigarettes later. For the present, I shall deal with the other manufactured tobacco products. In respect of branded biris, the present tobacco stage duty plus biri duty comes to about Rs. 3 per thousand biris; it is proposed to fix a consolidated rate of Rs. 3.60 per thousand branded biris. Unbranded biris produced by manufacturers of both branded and unbranded biris will pay the same duty. At present, unbranded biris are exempt from biri duty; but they are subject to tobacco stage duty which

works, to about ninety paise per thousand biris. It is proposed to levy a nominal consolidated duty of Rs. 1.60 per thousand on other unbranded biris. However, to provide relief to the small manufacturers of unbranded biris alone it is proposed to exempt manufacturers who produce only unbranded biris from payment of duty on their clearances of the first 60 lakh biris in a year. It is also proposed to make suitable upward duty adjustments in respect of chewing tobacco, snuff and smoking mixtures. It is also proposed to levy a duty of 20 per cent ad valorem on branded manufactured hookah tobacco.

112. As an interim measure, it is proposed to provide for suitable relief in product stage duty in the case of those products manufactured out of duty-paid unmanufactured tobacco except in respect of smoking mixtures and manufactured hookah tobacco.

113. Hon'ble Members will recall that the Indirect Taxation Enquiry Committee under Shri L. K. Jha submitted Part II of its final report in January, 1978. The Committee has indicated the broad lines on which rationalisation of the excise tariff should be attempted both in the short term as well as in the long term. I have given close and careful consideration to the Committee's recommendations. A major restructuring of the excise tariff has to be ruled out in view of the need for resources and on other pragmatic considerations. Also there is reason to apprehend that a major departure from the present pattern of excise taxation may upset the balance between different sectors of production. However, as part of the follow-up action on the Committee's recommendations, I have attempted to restructure the excise duty rates on a wide range of consumer and finished products.

114. Let me state at the outset that as a result of this restructuring, the number of effective excise duty rates have been reduced from 28 to 16 in respect of commodities covered by the present exercise. I have also availed of this opportunity to introduce further progression in the duty structure and stepped up the duty on quite a few luxury and semi-luxury items. Excise duties are being increased on cosmetics and toilet preparations (other than perfumed hair oil), from 63 per cent to 100 per cent, on air-conditioners from 105 per cent to 110 per cent, on parts of refrigerating and air-conditioning machinery from 105 per cent to 125 per cent, on stereo and hi-fi equipment from 36.75 per cent to 40 per cent, on higher priced television sets from 21 per cent to 30 per cent, on higher priced radios and radiograms from 36.75 per cent to 40 per cent. I have maintained the duty differential of 15 per cent ad valorem in respect of those electronic products where such duty differential exists for small scale units.

115. I have also taken this opportunity to step up suitably the duty rates on durable consumer articles on the consideration that the outlay on these items is mostly of a non-recurring nature and the incidence of duty is spread over a period of time. In this category, it is proposed to increase excise duties on pressure cookers from 10.5 per cent to 15 per cent, on steel furniture from 21 per cent to 25 per cent, on domestic electrical appliances from 26.25 per cent to 30 per cent, and on safes and strong boxes from 21 per cent to 35 per cent.

116. I have also selected some consumer items like soap, tooth paste, tooth brush and detergents, for increase in duties taking care, at the same time, to see that the goods produced by the small units in the decentralised sector are not adversely affected by this increase. Excise duties will go up on household and laundry soap from 5.25 per cent to 20 per cent, on low priced toilet soap from 10.5 per cent to 15 per cent, on high priced toilet soap from 15.75 per cent to 20 per cent, on detergents from 13.13 per cent to 20 per cent and on tooth paste from 10.5 per cent to 25 per cent. It is also proposed to impose a 25 per cent duty on tooth brushes. Let me state clearly that my objective in increasing the rates on these commodities is partly to ensure that the small-scale manufacturers, with the advantage of duty exemption, are able to increase their share of the market for these products.

117. Among food items, I have avoided imposing any further burden on articles of mass consumption such as processed edible oils or vanaspathi. I have, in fact, reduced the duty on vanaspathi by exempting it from special excise duty. However, I have considered items like prepared or preserved food, instant coffee, biscuits, processed cheese, cocoa powder, chewing gum and chocolate as fit for further increases, bearing

in mind the sections of the society that consume such items. Thus, excise duties are increased on instant coffee from 21 per cent to 25 per cent, on prepared or preserved food, biscuits and processed cheese from 10.5 per cent to 15 per cent, and on cocoa powder, chewing gum and chocolates from 10.5 per cent to 20 per cent. In aerated waters, it is proposed to increase the duty rate on plain soda from 15.75 per cent to 20 per cent. In respect of other aerated waters I propose to have two rates—one of 60 per cent for those containing caffeine and the other of 30 per cent for those not containing caffeine. It is also proposed to withdraw the present concessional rate applicable to clearances of the first 50 lakh bottles in a financial year. However, the existing exemptions in respect of aerated waters in favour of small manufacturers will continue.

118. In restructuring the duty rates on consumer products, I have reduced the incidence on a number of items by exempting them from special excise duty. I would like to make particular mention of the duty reduction from 42 per cent to 30 per cent on fluorescent lighting tubes, which are widely used for street lighting and which help in reducing the consumption of electricity. It is also proposed to extend the scope of the present excise exemption for low priced footwear valued upto Rs. 5 per pair to footwear valued upto Rs. 10 per pair.

119. I have also rationalised the rates applicable to personalised modes of transport, Mopeds, which are used by comparatively less affluent people and consume less fuel, will bear a lower duty of 10 per cent as against the existing duty of about 13.1 per cent. Scooters, motor cycles and three-wheelers will bear 20 per cent as against the existing level of 13.13 per cent, while cars will pay duty at 25 per cent as against the existing rate of 18.38 per cent. The concessional rate applicable to cars used as taxis and autorickshaws will be increased from 10 per cent to 15 per cent. The rate on commercial vehicles will also go up marginally from 13.1 per cent to 15 per cent as part of the scheme of rationalisation.

120. In manufactured inputs, I have mainly confined myself to streamlining the existing rates having regard to their usage and their relative importance. The details of these changes are contained in the Budget papers.

121. Another tax reform suggested by the Indirect Taxation Enquiry Committee is to extend proforma credit facilities in respect of the duty paid on inputs used in the manufacture of finished products. Presently, such facilities are available in a limited area. Wide extension of these facilities as recommended by the Committee would have major revenue implications apart from throwing additional administrative burden in working these procedures. However, industry has been urging that this measure be given a trial. I propose to extend, as an experimental measure, the provision of proforma credit to some of the products of the engineering industry, where the incidence of duty on inputs is perceptible. While doing so, I have also proposed upward rate adjustments in respect of some of the final products. The details of these changes are available in the Budget papers.

122. The net revenue effect of the proposals for restructuring the Central excise tariff, along with a few minor changes in some of the items affected, is a gain of about Rs. 100 crores in a full year.

123. I now turn to substantive proposals to raise resources.

124. On the excise side, the most important proposals relate to a few major products of the petroleum group. Hon'ble Members are aware that the OPEC countries have announced a phased programme of increase in the price of crude oil. We are still, to a significant extent, dependent on imports of crude oil and the anticipated increase in the out-flow of foreign exchange consequent on the increases in crude prices is substantial. After the initial drop in consumption of petroleum products in the wake of the steep increase in crude prices in the year 1973, consumption has registered a sizable upward trend. From the point of view of evolving a viable energy policy which minimises the strain on our foreign exchange resources, I have no doubt that it is essential to restrain the consumption of the more important petroleum products. My revenue proposals have been formulated keeping this important objective in mind.

125. It is proposed to raise the Central excise duty on motor spirit from the existing level of Rs. 2253.88 to Rs. 2750 per kilolitre. Since the bulk of the consumption of petrol is by the upper classes in society I have no regrets in doing this. I also propose to raise the duty on high speed diesel oil from the existing level of Rs. 404.04 to Rs. 500 per kilolitre because of the rapid growth in its consumption.

126. As Hon'ble Members are aware, kerosene was being used, in the past, to adulterate high speed diesel oil when there was a price differential in favour of kerosene. It has been our endeavour in the last few years to check this tendency by maintaining, as far as possible, parity between the rates of duty on these two products. Besides, we have had, in the recent past, to rely heavily on imports of kerosene. Bearing these considerations in mind, I propose to increase the duty on kerosene from the existing level of Rs. 408.19 to Rs. 500 per kilolitre. I also propose to effect a sympathetic increase in the rate of duty of liquified petroleum gas, which is primarily used as cooking fuel in urban and semi-urban areas, from the existing level of Rs. 262.50 per metric tonne to Rs. 400 per metric tonne.

127. My proposals relating to the petroleum products are expected to yield an additional revenue of Rs. 223.25 crores under Central excise and Rs. 55.7 crores under customs.

128. Next, it is proposed to increase the rate of duty on the residuary heading Item 68 of the Central Excise Tariff from the existing level of 5 per cent to 8 per cent ad valorem. This will yield an additional revenue of Rs. 100 crores. As Hon'ble Members are aware, there is already a provision for giving set off of the duty paid on goods falling under Item 68 which are used in the manufacture of other excisable goods. The increased levy should, therefore, not have any appreciable cascading effect.

129. As the House is aware, small scale manufacturers producing goods falling under Item 68, whose clearances of all excisable goods during the preceding year had not exceeded Rs. 30 lakhs, presently enjoy exemption from duty payable on their first clearances upto a value of Rs. 30 lakhs. There have been persistent representations that in computing the eligibility of a small scale unit for this concession, the value of goods falling under Items other than Item 68 should be excluded. There have also been demands that clearances for exports should be excluded so that the units in the small scale sector are encouraged to step up their export efforts. I accept the validity of these demands. Keeping these as well as the proposed increase in duty under Item 68 in view, I propose to rationalise the existing scheme of exemption. Under the revised scheme which would be effective from 1st April, 1979, small scale manufacturers, whose clearances for home consumption of goods falling under Item 68 in the preceding financial year did not exceed Rs. 30 lakhs would enjoy complete exemption from the duty payable under Item 68, on their first clearances of a value upto Rs. 15 lakhs; they would pay duty at 4 per cent, which is half of the rate of duty proposed for this item, on clearances between Rs. 15 lakhs and Rs. 30 lakhs.

130. As the Hon'ble Members are aware, the scheme of excise duty concession to encourage higher production in selected industries, which was announced in the year 1976, is due to expire on 31-3-1979. I do not propose to continue the scheme beyond this date. This withdrawal is expected to yield an additional revenue of Rs. 40 crores.

131. I have also taken this opportunity to review a number of existing notifications and I propose to modify or withdraw some of them. The details of this will be found in the Budget papers.

132. In my search for additional resources I have, of necessity, to fall back upon the old faithful, cigarettes. I have already referred to the withdrawal of the duty on tobacco at the unmanufactured stage which is borne by cigarettes. I now propose to adjust the rate structure on cigarettes. In such a way as to further secure an additional sum of Rs. 60 crores from this item. Taking into account the revenue expected to accrue from this measure and the recasting of the rate structure applicable to the manufactured tobacco products, which I have referred to earlier, the States' share in respect of additional excise duty in lieu of sales tax will go up by Rs. 18.31 crores a year.

133. As Hon'ble Members are aware, the excise duty mechanism has been used consciously to encourage the production of matches in the non-mechanised sector. I propose to carry this process farther by stepping up the duty on matches produced by the mechanised sector from the existing level of Rs. 4.83 per gross boxes of 50 matches to Rs. 9.20. I also propose to round off the existing level of duty applicable to the non-mechanised sector, other than cottage units, from the existing level of Rs. 4.52 to Rs. 4.50. As regards cottage sector units. It is proposed to reduce the duty applicable to them from Rs. 3.36 to Rs. 1.60. I am sure this package of measures will result in a further accelerated growth of the non-mechanised sector in general and cottage units in particular. The additional revenue yield from this measure is expected to be of the order of Rs. 8 crores during a year.

134. Machine-made carpets produced in a few organised units constitute an item of elite consumption. I can see no justification for encouraging this line of production when we have a large number of traditional carpet weavers whose skills have won international renown. I would not like the livelihood of these weavers to be threatened by the proliferation of machine-made carpets. I, therefore, propose to impose a duty of 30 per cent on such machine-made carpets. Handmade carpets will be totally exempt from this levy. The estimated additional yield from this proposal is Rs. 1.9 crores.

135. Consistent with the above approach, with a view to encouraging labour oriented non-power processing sector of the cotton textile industry, it is proposed to withdraw the concessional rate of 8 per cent ad valorem on power-processed white powerloom cotton fabrics of finer varieties so that such fabric also pay the same rate of 12 per cent ad valorem as is applicable to other power processed fabrics.

136. This Government is committed to the encouragement of the handloom sector. The competitive capacity of handloom fabrics in relation to fabrics produced by powerlooms and composite mills has to be improved further. It is therefore, proposed to increase the excise duty on cotton and cellulosic spun yarn of finer counts used by composite textile mills and powerlooms by about 10 per cent of the existing rates. Details of these changes are available in the Budget papers. Additional revenue expected from these measures is about Rs. 10 crores.

137. The special duties of excise imposed as a part of the 1978 Budget are due to expire on 31-3-1979. It is proposed to continue these levies for another year at the existing rate of 1/20th of the effective basic excise duties. However, it is proposed to exempt from this levy items in respect of which rates have been restructured as well as the new levies; the existing exemption in respect of electricity, coal and Item 68 will also be continued.

138. I shall now deal with the proposals concerning customs duties. The most important of them relates to withdrawal of the existing exemption from countervailing duties of customs applicable to imported goods, which attract classification under item 68 of the Central Excise Tariff. When this residuary entry was introduced in that Tariff in 1975, imported goods were exempt from the corresponding countervailing duty customs. This exemption which was initially granted when the excise duty on indigenous goods was 1 per cent ad valorem has continued, even though the rate has successively been stepped up to 5 per cent. As I have already stated, I have proposed a further increase in the Central excise duty under Item 68, from 5 per cent to 8 per cent ad valorem. In this context and as a measure of protection to the indigenous goods classifiable under Item 68, it is proposed to withdraw the existing exemption in respect of imported goods. In withdrawing this exemption, however, I have not proposed any change in the duty in regard to project imports and also the items of machinery on which the customs duty was, in the recent past, reduced to 25 per cent ad valorem on the consideration that such machinery is not indigenously produced. This measure will yield an additional revenue of Rs. 96 crores by way of countervailing duty.

139. In the context of the sizable gap between supply and demand of edible oils, substantial imports of these oils have taken place in the past and are continuing. As a means of assuring remunerative prices to indigenous producers of oil seeds, it is proposed to levy basic customs duty on palm oil, rapeseed oil, soyabean oil, sunflower oil and palmolein oil at 12-1/2 per cent ad valorem. They will, however, be

exempt from auxiliary and countervailing duties. This measure is expected to yield an additional revenue of Rs. 33.5 crores.

140. It is proposed to continue the auxiliary duties of customs for the next financial year at the existing levels.

141. Taking Union excise duties and customs duties together, my proposals will lead to a net revenue gain of Rs. 606.14 crores in a full year, of which Rs. 413.15 crores will accrue to the Centre and Rs. 192.99 crores to the States.

142. Where changes are proposed to be made by notifications, effective from the 1st March, 1979, copies of such notifications will be laid on the Table of the House in due course.

143. Members are aware that in respect of every international journey paid for in Indian currency, Foreign Travel Tax is being collected from passengers. In order to simplify the administration of the tax, and to guard against the possibility of evasion, I propose to revise the scheme and replace the ad-valorem levy with a specific one. The new arrangements will be brought into force as soon as possible after legislation in this behalf is enacted. This measure will not have any significant revenue effect.

144. I have now a few words to say on behalf of my colleague, the Minister of Communications. As Hon'ble Members are aware, the unit costs of a number of our postal services exceed the revenue they fetch. Moreover, the modernisation of telecommunication services involves large capital investment. These factors necessitate an increase in postal and telecommunication tariffs. A memorandum showing the proposed tariffs is being circulated along with the Budget papers. The letter card (inland letter) and the letter will cost five paise more. The rate for the post card has been left untouched. As regards telecommunication tariffs, the ordinary telegram of 8 words will cost Rs. 2.25 as against Rs. 2 at present and each additional word will cost 30 paise as against 25 paise at present. The rate of Press telegrams will however remain unchanged. Local call charges, beyond 1750 calls per quarter, will be 40 paise per call, as against 30 paise at present. I will not go into other details which are given in the memorandum. The tariff revisions, which will be given effect to from a date to be notified by the Government after the Finance Bill is passed, are estimated to result in additional revenue of

Rs. 57.96 crores per annum. The yield during 1979-80 is placed at Rs. 48.30 crores and has been accounted for in estimating the internal resources of the Posts and Telegraphs.

145. Our tax effort will bring in about Rs. 665 crores, of which Rs. 205 crores will accrue to the States leaving Rs. 460 crores with the Centre. Taking also into account Rs. 160 crores of accretions compulsory deposits by income-tax payers, there will be a residual deficit of Rs. 1355 crores, which I propose to leave uncovered. I have assessed carefully the inflationary potential of a deficit of this size. The large food output of the current year, the large stocks of food and other commodities we have, the large volume of foreign exchange reserves and a continuation of the current supply management and restrictionist monetary policies give me confidence that we shall be able to maintain reasonable price stability in the coming year also.

146. With this I have come to the end of my labours. I have attempted in this budget to put the maximum emphasis on agricultural and rural development and labour intensive industry, because it is now accepted by all that only that way can we eradicate poverty and unemployment in the country. I have, however, not neglected large industry and infrastructure in the process. On the contrary, I have positively encouraged them. But I have no sympathy with those industries which cater to the wants of the rich. We can have no room for production which caters to the rich and is thus a visible manifestation of the disparities which exist in our society.

147. The elimination of the kind of poverty which exists in our country cannot be achieved overnight. It is a long process which involves large investment through the mobilisation of surplus resources wherever they exist in society, better organisation and the development and transfer of appropriate knowhow to millions of small persons engaged in agriculture and allied occupations and village industries throughout the country. The ultimate objective is not merely to raise the standard of living of the poor but to build a society of men and women with skills, resources, imagination, and above all, hope. I like to think that this budget is a small step in that direction. But its success really depends upon a national consensus about the desirability of the objective and the need to work hard for it and a willingness on the part of the powerful and affluent sections of society to make the necessary sacrifices. I seek the help of this House in achieving such a consensus and securing the required sacrifices.

A. C. TIWARI, Jt. Secy.

